घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 116- बुधवार 25- फरवरी 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

संक्षिप्त समाचार

हल्द्वानी अतिक्रमण विवाद...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा...जमीन रेलवे की है,अतिक्रमणकारी शर्तें तय नहीं कर सकते

नई दिल्ली,24 फरवरी 2026। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तराखंड विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह एक शिविर लगाए, ताकि रेलवे परियोजना के लिए आवश्यक सरकारी जमीन पर रह रहे और बेदखली का सामना कर रहे परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पुनर्वास के लिए आवेदन कर सकें। याचिकाकर्ताओं के आग्रह पर कोर्ट ने कहा कि यह शिविर 15 मार्च के बाद लगाया जाए,क्योंकि उन्होंने इसे रमजान के महीने के बाद आयोजित करने की मांग की थी। शीर्ष कोर्ट ने नैनीताल के जिला कलेक्टर और अन्य राजस्व अधिकारियों को आवश्यक सहायता देने का निर्देश दिया। यह पूरी प्रक्रिया 31 मार्च से पहले पूरी की जानी है। शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा कि जिला कलेक्टर हर परिवार की योजना के तहत पात्रता तय करें और अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्य कांत और जॉयमाल्या बागची की बेंच दिसंबर 2022 में उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी,जिसमें हल्द्वानी में सार्वजनिक जमीन पर कथित रूप से कब्जा करने वाले करीब 50 हजार लोगों को हटाने का निर्देश दिया गया था। जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी और इस अंतरिम आदेश को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है।

एआई समिट हंगामा...

उदय भानु 4 दिन हिरासत में

नई दिल्ली,24 फरवरी 2026। एआई इम्पैक्ट समिट हंगामा मामले में इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है। उन्हें मंगलवार को सुबह तिलक मार्ग थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी और आरोप लगाया कि चिब ही घटना के मास्टरमाइंड हैं। प्रदर्शनकारी उनके निर्देश पर भारत मंडपम में आयोजित समिट में घुसे थे। चिब ने ही उनको लॉजिस्टिक हेल्प की थी। इधर एआई समिट मामले की जांच दिल्ली पुलिस की इंटर-स्टेट क्राइम ब्रांच टीम को सौंपी गई। चिब की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने लिखा कि चिब की गिरफ्तारी असंवैधानिक और तानाशाह नरेंद्र मोदी की सनक का नतीजा है। राहुल ने लिखा कि कांग्रेस के 'बब्बर शेर' साथियों पर गर्व, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के खिलाफ निडर होकर देश के हित में आवाज उठाई।

कैबिनेट की मंजूरी...केरल का नाम बदलकर होगा केरलम

रेल-मेट्रो और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए 12,236 करोड़ मंजूर

नई दिल्ली,24 फरवरी 2026। पीएम नरेंद्र मोदी के नए ऑफिस सेवा तीर्थ में मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। इसमें कुल 12,236 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश,बिहार और झारखंड में तीन रेल प्रोजेक्ट समेत कुल 8 फैसले लिए हैं। बैठक में पावर सेक्टर में सुधारों पर पॉलिसी से जुड़े फैसले हुए और केरल सरकार के राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। केरल में अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। कैबिनेट ने तीन नए रेल प्रोजेक्ट के तहत गोंदिया-जबलपुर रेल लाइन के डबलिंग, गम्हरिया-चांडिल और पुनारख-किऊल के बीच तीसरी-चौथी रेल लाइन को मंजूरी दी है। साथ ही श्रीनगर में एक नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनेगा और अहमदाबाद मेट्रो के फेज 2 बी का एक्सटेंशन होगा।

प्रस्ताव केरल विधानसभा को भेजा जाएगा

कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब राष्ट्रपति 'केरल (नाम में बदलाव) बिल,2026' को संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत केरल विधानसभा की राय के लिए भेजेंगे। विधानसभा की राय मिलने के बाद, सरकार संसद में बिल पेश करेगी। संसद से पास होने पर राज्य का नाम आधिकारिक रूप से केरलम हो जाएगा। केरल विधानसभा से 24 जून 2024 को प्रस्ताव पास हुआ था। इस प्रस्ताव के मुताबिक केरल का असल में मलयाली भाषा में नाम केरलम है। हिंदी और दूसरी भाषाओं में इसे केरल कहा जाता है। नाम बदलने का उद्देश्य केरल राज्य की पहचान, भाषा, संस्कृति और विकास को बढ़ावा देना है।

केंद्र ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल बनाने की मंजूरी दी...

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सिविल एन्क्लेव के विस्तार को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर लगभग 1,677 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इसके पूरा होने पर हवाई अड्डे की क्षमता में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में नए सेवा तीर्थ में मंगलवार को आयोजित मंत्रिमंडल की प्रथम बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। वैष्णव ने बताया कि 73.18 एकड़ क्षेत्र में 71,500 वर्ग मीटर का नया टर्मिनल भवन बनाया जाएगा, जिसमें 20,659 वर्ग मीटर मौजूदा संरचना का उपयोग होगा। विमान पार्किंग क्षेत्र का विस्तार कर 15 विमान पार्किंग बे बनाए जाएंगे, जिनमें एक वाइडबॉडी (कोड ई) बे भी शामिल होगा।

कैबिनेट ने 9,072 करोड़ की तीन रेल मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को दी मंजूरी...

केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने मंगलवार को रेल मंत्रालय की तीन महत्वपूर्ण मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 9,072 करोड़ रुपये है और इन्हें वर्ष 2030-31 तक पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीईए की हुई बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्वीकृत परियोजनाओं में गोंदिया-जबलपुर दोहरीकरण,पुनारख-किऊल तीसरी एवं चौथी लाइन तथा गम्हरिया-चांडिल तीसरी एवं चौथी लाइन शामिल हैं। ये तीनों परियोजनाएं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के आठ जिलों को कवर करेंगी और इनके माध्यम से भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 307 किलोमीटर की वृद्धि होगी।

लोकसभा अध्यक्ष ने 64 पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स बनाए

हर ग्रुप में एक लीडर समेत 11 सांसद,फ्रांस में थरूर,जापान में अखिलेश यादव नेतृत्व करेंगे

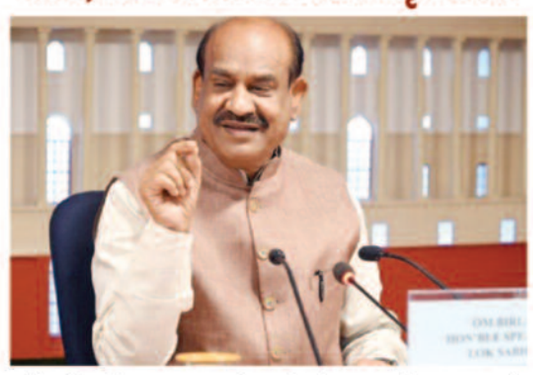

नई दिल्ली,24 फरवरी 2026। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार को 64 देशों के साथ पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स का गठन किया है। इन ग्रुप्स का मकसद दूसरे देशों के साथ संसदीय कूटनीति को मजबूत करना और वैश्विक मंच पर भारत की संसद की एकजुट लोकतांत्रिक आवाज पेश करना है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी ने भारत और अन्य देशों के बीच संवाद बढ़ाने के लिए PFG बनाने का प्रस्ताव दिया था। अब लोकसभा अध्यक्ष ने इसका गठन किया है। 64 ग्रुप्स में लोकसभा और राज्यसभा के कुल 704 सांसद हैं। हर ग्रुप में एक लीडर और 10 सदस्य हैं। इनमें भाजपा के सबसे ज्यादा 30 ग्रुप लीडर हैं। कांग्रेस के 10, समाजवादी पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और तृणमूल कांग्रेस के 3-3 सांसद ग्रुप लीडर बनाए गए हैं। भाजपा की तरफ से ग्रुप लीडर्स में हेमा मालिनी, मनोज तिवारी, निशिकांत दूबे जैसे बड़े नाम शामिल हैं। कांग्रेस से शशि थरूर,TMC से अभिषेक बनर्जी और AIMIM चीफ असदुद्दीन औवेसी भी ग्रुप लीडर बनाए गए हैं। हालांकि,PFG के सदस्य कैसे काम करेंगे, अभी इसकी औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है।

तेलंगाना में चार माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण...

हैदराबाद,24 फरवरी 2026। प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) के चार वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को तेलंगाना में आत्मसमर्पण कर दिया और राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शिवधर रेड्डी की उपस्थिति में मुख्यधारा में लौट आए। पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने वालों में पोलित ब्यूरो सदस्य टिप्पिरी तिरुपति उर्फ देवजी उर्फ कुम्मा दादा,सेंट्रल कमेटी सदस्य मल्लराजी रेड्डी उर्फ संग्राम उर्फ रंगाराम, तेलंगाना स्टेट कमेटी सचिव बड़े चोक्का राव उर्फ दामोदर उर्फ जगन तथा स्टेट कमेटी सदस्य नून नरसिम्हा रेड्डी उर्फ गंगन्ना उर्फ रन्ना दादा शामिल हैं। डीजीपी शिवधर रेड्डी ने इस मौके पर आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि पिछले दो वर्षों में कुल 591 माओवादी मुख्यधारा में लौट चुके हैं। इनमें चार सेंट्रल कमेटी सदस्य, 16 राज्य कमेटी सदस्य,26 डिवीजन कमेटी सदस्य एवं सचिव,85 एसीएस तथा 60 अन्य सक्रिय सदस्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जन्मे और पले-बढ़े 11 माओवादी अभी भी छिपे हुए हैं, जिनमें से कुछ वार्ता कर रहे हैं और उनके भी जल्द आत्मसमर्पण करने की संभावना है। डीजीपी ने बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के आह्वान पर कई माओवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर सार्वजनिक जीवन में लौटने की इच्छा जताई है। सरकार आत्मसमर्पण करने वालों को घोषित इनाम राशि और पुनर्वास पैकेज तत्काल उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति स्पष्ट है-जो हथियार छोड़ेंगे,उन्हें सम्मानजनक जीवन दिया जाएगा।

मोदी ने अमेरिका से देश बेचने की डील की : राहुल

पीएम पर एपस्टीन-अडाणी के केस का दबाव,भोपाल में कांग्रेस की किसान महाचौपाल...

भोपाल,24 फरवरी 2026। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से देश बेचने की डील की। उन पर एपस्टीन और अडाणी के केस का दबाव है। इस वजह से उन्होंने हिंदुस्तान और किसानों का डेटा अमेरिका को बेच दिया। राहुल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बोल रहे थे। कांग्रेस ने भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के विरोध में किसान चौपाल बुलाई थी। इस दौरान राहुल ने कहा, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। मैं चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर बात रखना चाहता था। राहुल ने कहा- मैंने लोकसभा में पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की बात रखी थी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जब चीनी घुसपैठ हुई थी तो उन्हें हिंदुस्तान की सरकार ने अकेला छोड़ दिया।

खड़गे बोले...मोदीजी कांग्रेस शासन में पैदा हुए,उनका अपना नाम बदलना चाहिए

खड़गे ने कहा... किसान जो फल उगाते हैं, उसका भी दाम नहीं मिलेगा। ये सब बातें अमेरिका के साथ किए गए एग्रीमेंट में है। मोदीजी ट्रंप की गुणगान करने वाले हैं। मनरेगा का नाम बदल दिया। मोदी का सिर्फ काम है,नाम बदलो। रास्ते का नाम बदलो,योजनाओं का नाम बदलो। मोदीजी खुद का नाम बदल लें,क्योंकि वह कांग्रेस शासन काल में पैदा हुए। खड़गे ने कहा... ब्राजील का प्रधानमंत्री आकर कहते हैं कि हिम्मत मत हारो मोदी जी,किसान के लिए लड़ो। मोदी जी के पास हिम्मत नहीं है। वह ट्रंप के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। छोटे देश किसानों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मोदी जी चुप रहते हैं। खड़गे ने कहा...तेल खरीदने पर भी मोदी जी ने ट्रंप की बात मानी। ट्रंप कहते हैं ऐसा करो तो मोदी जी कहते हैं यश सर। मोदी जी बस यश सर कहने में लग गए हैं। ट्रंप की बात मोदी जी मान रहे हैं।

राहुल गांधी ने कहा...मोदी ने किसानों को खत्म किया,हमारा डेटा दिया...

राहुल गांधी ने कहा..मोदी ने किसानों को खत्म किया। हमारा डेटा दिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म किया। अब कहते हैं हम बांग्लादेश की मदद करेंगे। टेक्सटाइल में जीरो परसेंट टैक्स लगाएंगे। हमारा मंत्री कहता है कि हिंदुस्तान अमेरीका से कपास खरीदेगा तो टैक्स जीरो। ट्रंप कहता है कि हर साल हिंदुस्तान को नौ लाख करोड़ रुपए का माल अमेरीका से खरीदना पड़ेगा। पांच साल के लिए। बात समझिए। ऐसे में हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा? मोदी ने दबाव में सब दे दिया। मैं पूछता हूं आपने लिया क्या? मुझे एक चीज बता दो। कुछ नहीं लिया। पहले से ज्यादा टैक्स हम देंगे। हमारा पहले कम था। हम कोई इंपोर्ट की गारंटी नहीं दी। मैं लिखकर दे सकता हूं, अगर मोदी पर दबाव और धमकी नहीं होती तो वे ऐसा नहीं करते। राहुल ने कहा... ये जो बेवा है अपनी छवि और राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए किया। लेकिन वे बच नहीं सकते। उनको कोई बचा नहीं सकता। मैं कांग्रेस के बब्बर शेरों से कहता हूं, आप किसी से डर नहीं सकते। आपने इंडस्ट्री बनाई, मोदी ने खत्म किया।

स्वास्थ्य सेवाएं देते समय अपनी जिम्मेदारी निभाएं : राष्ट्रपति मुर्मू

मुंबई,24 फरवरी 2026। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को कहा कि सभी के लिए सस्ती और विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। मुर्मू मुंबई के लोक भवन में पीडी हिंदुजा अस्पताल की ओर से आयोजित 'सेविंग लाइव्स एंड बिल्डिंग अ हेल्दीयर भारत' अभियान की शुभारंभ के अवसर पर संबोधित कर रही थीं।

सेवा देते समय सामाजिक जिम्मेदारी का भी ध्यान रखें :

उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि भारत वैश्विक स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में प्रतिष्ठा हासिल करेगा। राष्ट्रपति ने निजी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों से कहा कि वे स्वास्थ्य सेवाएं देते समय अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का भी ध्यान रखें।

चिकित्सा क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रही तकनीक और एआई

मुर्मू ने कहा...स्वस्थ भारत के निर्माण में सरकार के साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों की भी भूमिका अहम है। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा जन-जन तक पहुंचे इसके लिए सब को मिलकर प्रयास करना है। राष्ट्रपति ने कहा कि तकनीक और एआई अन्य क्षेत्रों की तरह चिकित्सा के क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। चिकित्सा के हर क्षेत्र में इनका प्रयोग किया जा रहा है।

किफायती चिकित्सा प्रदान करना बेहद जरूरी

मुर्मू ने कहा..दवा और उपकरण का देश में ही निर्माण देशवासियों को किफायती चिकित्सा प्रदान करने के लिए बेहद जरूरी है। मेक इन इंडिया और पीएलआई जैसी पहल इस दिशा में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।

युद्धाभ्यास 'खड़ग शक्ति' में दिखी भारत की सैन्य शक्ति,युद्ध कौशल का जबरदस्त प्रदर्शन

बीकानेर,24 फरवरी 2026। एशिया की सबसे बड़ी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 'खड़ग शक्ति' युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय सेना की सैन्य शक्ति एक बार फिर देखने को मिली। सेना ने आधुनिक और पारंपरिक युद्ध कौशल का जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस दौरान दस हजार फीट की ऊंचाई से पैराट्रूपरों की सामरिक छलांग,चेतक और चीता हेलीकॉप्टरों द्वारा त्वरित एम्युनिशन आपूर्ति व रेकी,हथियारों से लैस अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की सटीक मार कार्रवाई,स्वॉर्म और लॉजिस्टिक ड्रोन का उपयोग के साथ-साथ तोपखाने की समन्वित फायरिंग का प्रदर्शन हुआ।

अभ्यास में ड्रोन ऑपरेशन्स, दिव्यास्त्र बैटरी, अग्निबाण रेजीमेंट, अश्नी योद्धा सिस्टम, स्मर्च रॉकेट सिस्टम और इंटीग्रेटेड आर्टिलरी फायरपावर का प्रदर्शन किया गया। अंतिम चरण में पश्चिमी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार खटियार और टू कोर कमांडर जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर की उपस्थिति में संयुक्त युद्धाभ्यास और एयरबोर्न ऑपरेशन का लाइव प्रदर्शन हुआ। 8 से 10 हजार फीट की ऊंचाई से पैराड्रॉप, सटीक आर्टिलरी स्ट्राइक और दुश्मन क्षेत्र में घुसकर कार्रवाई का सिमुलेशन इस अभ्यास की खास झलक रही। वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने अभ्यास का निरीक्षण करते हुए विभिन्न चरणों की समीक्षा की। लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर ने बताया कि युद्धाभ्यास के दौरान महाजन की रेतीली धरा पर सेना की तोपें और टैंको ने अपनी गर्जना से आसमान गुंजायमान कर दिया और ड्रोन तकनीक के उपयोग पर विशेष फोकस किया गया। युद्धाभ्यास में नाइट फायरिंग (रात्रि कालीन युद्धाभ्यास) पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसके माध्यम से अंधेरे में भी दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों को अचूक निशानों से ध्वस्त करने का अभ्यास किया गया।

आधुनिक युद्ध के बदलते स्वरूप को देखते हुए इस अभ्यास में ड्रोन तकनीक का व्यापक उपयोग किया गया,जिससे निगरानी से लेकर सटीक हमलों तक में ड्रोन की भूमिका प्रदर्शित की गई। अभ्यास की एक प्रमुख विशेषता ड्रोन आधारित निगरानी और आक्रमण प्रणाली रही।

गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे अविमुक्तेश्वरानंद....जल्द हो सकती सुनवाई

प्रयागराज,24 फरवरी 2026। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुका है। उधर गिरफ्तारी से बचने के लिए अविमुक्तेश्वरानंद ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। अधिवक्ता राजर्षि गुप्ता, सुधांशु कुमार और श्री प्रकाश के द्वारा ये जमानत याचिका दाखिल की गई है,जिस पर जल्द सुनवाई हो सकती है। बता दें कि तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने 173 (4) के तहत जिला कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इस पर एडीजे रेप एंड पॉक्सो स्पेशल कोर्ट विनोद कुमार चौरसिया ने झूंसी पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया था। कोर्ट के इस आदेश के अनुपालन में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी और दो-तीन अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर बीएनएस की धारा 351(3),लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा और 17 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

पश्चिम बंगाल एसआईआर...ओडिशा-झारखंड के सिविल जज करेंगे वेरिफिकेशन में मदद

सुप्रीम कोर्ट बोला...इनका खर्च चुनाव आयोग उठाए,80 लाख दावों का निपटारा बाकी

नई दिल्ली,24 फरवरी 2026। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में सामने आए 80 लाख क्लेम निपटाने के लिए 2 राज्यों से सिविल जजों को तैनात करने की परमिशन दे दी है। कोर्ट ने आदेश दिया कि कलकत्ता हाईकोर्ट पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट एसआईआर प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए झारखंड-ओडिशा के सिविल जजों की मदद ले सकता है। सीजेआई सूर्यकांत,जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने चुनाव आयोग से कहा कि वह 28 फरवरी को बंगाल की फाइनल एसआईआर लिस्ट पब्लिश कर सकता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वेरिफिकेशन प्रोसेस आगे बढ़ता है तो पोल पैनल सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी कर सकता है। इससे पहले 20 फरवरी को,पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच चल रही खींचतान से निराश होकर कोर्ट ने एसआईआर प्रोसेस में पोल पैनल की मदद के लिए मौजूदा और पूर्व जिला जजों को तैनात करने का निर्देश जारी किया था। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को लिखे लेटर में बताया था कि 80 लाख लोगों के क्लेम से निपटने के लिए 250 डिस्ट्रिक्ट जजों को 80 दिन लग सकते हैं।

संपादकीय

लगातार कठिन होता जा रहा संसद का चलना

लोकसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के सांसदों का निलंबन तब किया,जब वे वेल में जाकर लगातार अध्यक्ष की ओर कागज फेंक रहे थे,कोई आदेश या नियमन नहीं मान रहे थे। सदन संचालन के नियम और परंपरा हैं। उन्हें रौंदने पर उतारू लोगों के विरुद्ध अध्यक्ष को फैसला करना ही पड़ेगा...

भारत की राजनीति आज ऐसी अवस्था में पहुंच गई है,जिसकी कल्पना नहीं की जाती थी। यह भारत के संसदीय इतिहास की अत्यंत गंभीर स्थिति है,जब लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया,तो उसके समानांतर विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विरुद्ध सब्सटेंसिव मोशन। राहुल गांधी के विरुद्ध भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सब्सटेंसिव मोशन लाने की मांग की है। भाजपा ने पहले राहुल गांधी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की बात की थी, किंतु अब सब्सटेंसिव मोशन लाने की पहल की है। सब्सटेंसिव मोशन विशेषाधिकार हनन से ज्यादा गंभीर होता है। सब्सटेंसिव मोशन स्वतंत्र प्रस्ताव होता है,जिसमें किसी सांसद के विरुद्ध स्पष्ट निर्णय सामने आता है। इस प्रस्ताव पर बहस और मतदान होता है तथा पारित होने पर सदन का आधिकारिक रुख और मत प्रकट होता है।

यानी संबंधित सांसद का आचरण और चरित्र संसद के अनुकूल है या नहीं,उन्हें सांसद होना चाहिए या नहीं,उन्हें भविष्य में चुनाव लड़ने देना चाहिए या नहीं आदि। इसके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और सदन की सदस्यता भी जा सकती है। चुनाव आयोग को उन्हें चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने की अनुशंसा भी की जा सकती है। जो भी हो,अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस मिलने के बाद से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में आना बंद कर दिया। अविश्वास प्रस्ताव के बाद बहस और परिणाम तक लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं कर सकते,लिहाजा उन्होंने यह निर्णय लिया है। यही बात किसी सांसद या विपक्ष के नेता पर लागू नहीं होती। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव या सब्सटेंसिव मोशन स्वीकृत होने के बावजूद संबंधित सदस्य हिस्सा ले सकते हैं। उन्हें अपना पक्ष रखने का समय दिया जा सकता है।

लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर नौ मार्च को बहस होने की संभावना है। उसी दौरान यह पता चलेगा कि राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंसिव मोशन स्वीकृत होता है या नहीं? चूंकि लोकसभा में भाजपा नेतृत्व वाले राजग को बहुमत है इसलिए ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। यह बात सब्सटेंसिव मोशन पर लागू नहीं होती। बहुमत के आधार पर राजग राहुल गांधी के विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव पारित कर सकता है। हालांकि कांग्रेस में उनके समर्थकों में इससे कोई परेशानी नहीं दिखाई देती। उलटे वे यह कहते हुए प्रफुल्ल हैं कि संसद में एजेंडा तो राहुल गांधी ही सेट कर रहे हैं और अब सब्सटेंसिव मोशन के बहाने बहस भी उन्हीं के इर्द-गिर्द रहेगी। इससे सहज से अनुमान लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी और उनके इर्द-गिर्द के रणनीतिकार किस दिशा में जा रहे हैं। अगर उनकी नजर में यही सही अर्थों में राष्ट्रीय एजेंडा निर्धारित करना है तो ऐसी कांग्रेस का भगवान ही मालिक है। राहुल गांधी अपने राष्ट्रीय दायित्वों की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं।

लगता है कि कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि लोगों में उनके प्रति सहानुभूति पैदा हो और वे इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करें, लेकिन कांग्रेस के लोग जिस तरह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के विरुद्ध अभियान चलाते रहे हैं उसका क्या? उनकी बेटी के सिविल सर्विस पास होने तक पर प्रश्न उठाए गए थे? कांग्रेस की महिला सांसदों द्वारा उनको लिखा गया पत्र तो और शर्मनाक है। कांग्रेस के सांसद लोकसभा अध्यक्ष के लिए ऐसी कठिन स्थिति पैदा करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें फैसला लेने में ही समस्या हो। ओम बिरला यहां व्यक्ति नहीं लोकसभा अध्यक्ष जैसे गरिमापूर्ण पद पर हैं।

उनसे व्यक्तिगत मतभेद हो सकता है,उनसे नापसंदगी भी होगी,पर पद का सम्मान करने और विश्वास करने का प्राथमिक दायित्व भी नेता और संसद न निभाएं,तो यह शर्मनाक है। अगर राहुल गांधी के समर्थकों को लगता है कि संसद में चर्चा और बहस का एजेंडा सेट करना ही बड़ी राजनीतिक उपलब्धि है, तो कुछ दिन पहले एसआइआर एवं चुनाव आयोग के संदर्भ में भी उन्होंने ऐसी ही स्थिति पैदा की थी। उन्होंने अपनी ओर से पूरी तैयारी के साथ एसआइआर और चुनाव आयोग को कठघरे में खड़ा किया,बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की, लेकिन बिहार चुनाव परिणाम में उन्हें मुंह की खानी पड़ी। महाराष्ट्र चुनाव में अदाणी मुद्दा उनके लिए सर्वोपरि था,लेकिन वहां भी करारी हार हुई।

लोकसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के सांसदों का निलंबन तब किया, जब वे वेल में जाकर लगातार अध्यक्ष की ओर कागज फेंक रहे थे,कोई आदेश या नियमन नहीं मान रहे थे। सदन संचालन के नियम और परंपरा हैं। उन्हें रौंदने पर उतारू लोगों के विरुद्ध अध्यक्ष को फैसला करना ही पड़ेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस और आक्रामक हो गई है। वह नहीं चाहती कि एक दिन भी संसद में सामान्य स्थिति रहे और सदन सुचारु रूप से चले। राहुल ने राष्ट्रपति अभिभाषण से संबंधित मुद्दे पर किसी सत्र में भाषण नहीं दिया। वह मनगढ़ंत विषय लेकर आते हैं और उसे सदन में रखते हैं तथा अध्यक्ष के रोकने पर उन्हें आरोपित करते हैं। इस तरह के व्यवहार में कोई लोकतांत्रिक रास्ता निकल नहीं सकता।

समाज सृजन में दादा मुन्ना दास की योगदान और महत्व...

लक्ष्मीनारायण लहरे,साहिल,
सारंगढ़,रायगढ़,छत्तीसगढ़

समाज में फैली कुरीतियों को लेकर रचनाकार उस अंतिम व्यक्ति के साथ होता है जहाँ पर हर किसी का वश नहीं चलता और उस लडाई में लेखनी से संवेदनशीलता दिखाने के साथ साथ खडा भी रहता है । अपने अंतस से समाज में परिवर्तन लाने को आतुर रहता है जितना भी गुंजाईस हो हर शक्ल में उपस्थिति देने का प्रयास करता है,ठीक उसी प्रकार समाज में सामाजिक समरसता ,कुरीतियों,विषमता की चरम सीमा को विभेदन करने इस भारत वर्ष में ज्ञानी ,संत,महापुरूष जन्में और समाज को राह दिखाने का प्रयास किये समाज में परिवर्तन लाये लोगों को जागरूक किये जिन्हे इतिहास में जगह मिली और उन्हे याद करके आज भी समाज अपने आपको धन्य और गौरवांनित मानता है ।

आज भी समाज अलग-अलग पंथ ,जाति,धर्म,समुदाय में बंटे हैं फिर भी एक दूसरे पंथ,धर्म,समुदाय का आदर और सम्मान करतें हैं । समाज में एकता है । जाति,धर्म ,पंथ,समुदाय अनेक होने के बाद भी इंसान सभी वर्ग के संत ,ज्ञानी,महापुरूषों का सम्मान और आदर करते हैं संत बाबा गुरूघासी दास जी,कबीरजी पुजे जाते हैं उनकी सामाजिक समरसता का गुणगान होता है जो किसी से छुपा नहीं है जिन्होने समाज को दिशा दी लोगों को जागरूक किये और समाज के प्रेरणा बने ।

सामाजिक समरसता के संवाहक युवाओं के प्रेरणा स्त्रोत दादा मुन्ना दास से रूबरू करना चाहूँगा जो इतिहास के पन्ने में कहीं गुम हो गई जो अपने नई पिढी के लिए आगे आकर समाज के लिए जो योगदान दिये वास्तव में सराहनीय था । दादा मुन्ना दास लहरे का जन्म छत्तीसगढ के रायगढ़ जिले के वर्तमान में नव सृजित जिला सारंगढ़ - बिलाईगढ़ जिला के ऐतिहासिक नगरी कोसीर गांव के किसान परिवार में पंचम दास के घर सन 25 फरवरी 1926 को हुआ था । पंचम दास गांव के सभ्रांत किसान थे पढे लिखे कम थे । संत बाबा गुरूघासी दास जी के अनुयायी थे । उनके संदेशों-उपदेशों का उनके परिवार में असर था और बाबा के उपासक थे । मुन्ना दास जी का बाल्यकाल कुछ खास नही रहा अपने पिता के एकलौते पुत्र थे सन 1933 में जब वे सात वर्ष के हुए तब उनकी दाखिला गांव के ही बालक स्कूल में करायी गई बालक स्कूल का स्थापना सन 1908 में हुआ था । कोसीर गांव में पढने दुर दराज के गांव के भी लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे । आजादी के पहले गांव देहात में रहने वाले कम परिवार के ही लोग स्कूल में दाखिला लेते थे और दाखिला हो भी

जाती थी तो शिक्षा नहीं ले पाते थे,वैसा ही हाल दादा मुन्ना दास का था दाखिला तो हुए पर स्कूल पढने बहुत कम जाते थे।लगातार अनुपस्थिती के कारण दाखिल खारिज से नाम हटा दिया गया और स्कूल जाना बंद कर दिये और नहीं पढ पाये और खेती किसानी के काम में पिता का साथ देने लगे,बाल्यकाल में ही विवाह का प्रचलन था और ओ भी विवाह के बंधन में बंध गए। जैसे तैसे होस संभाले थे तब ओ लगभग 19 वर्ष रहा होगा । पत्नी की तबियत खराब रहती थी एक दिन तबियत बहुत बिगड़ गई और गुजर गई उनके दो पुत्र थे अभी चलना ही सिखे थे बच्चो की देख भाल करने में परेशानियों का सामना करना पढ रहा था तब उनका विवाह बलौदा बाजार,वर्तमान जिला सारंगढ़ के टीहलीपाली के गौटिया परिवार के बेटी श्रीमती रामबाई जी से हुई उनकी पहले पत्नी के दो पुत्र थे ओ भी बडे होने लगे और श्रीमती रामबाई ने भी एक पुत्री को जन्म दिया देखते ही देखते परिवार बढ़ गया और राम बाई जी के दो पुत्र तीन पुत्री हुई रामबाई काम काजी महिला थी । दादा मुन्ना दास के चार पुत्र और तीन पुत्री में दो पुत्र समय के पहले ही चल बसे। परिवारिक जीवन उथल पुथल भरा रहा। कोसीर गांव में आजादी के बाद कक्षा 6 वीं तक की पढाई होती थी उस समय मिडिल स्कूल में हिन्दी की पढाई होती थी अंग्रेजी की पढाई नही होती थी। 15 अगस्त 1947 के लगभग एक दशक के बाद सन 1956 में 15 अगस्त को स्कुली बच्चे प्रभात फेरी में नारा लगा रहे थे अंग्रेजी पढाओ बालक बचाओ। गांव के शिक्षक रहे वरिष्ठ साहित्यकार तीरथ राम चन्द्रा जी बताते हैं तब नारा को सुनकर दादा मुन्ना दास गांव के चैक में रूके और नारा की जानकारी लिये वो उस समय खेत से हल लेकर घर को लौट रहे थे वह चैक जो अभी वर्तमान में डॉ. अम्बेडकर चैक के नाम से जाना जाता है जो अब हृदय स्थल ही । बचपन में न पढ पाने की दुख ने उनके मन में संवेदना भर दी और स्कूल में अंग्रेजी पढाने के लिए शाला विकास समिति में उस समय के तत्कालीक प्रधानाध्यापक चन्दन राम यादव को अपने जमीन बेजकर 10 हजार रूपये दिये तब स्कूल में अंग्रेजी की पढाई और स्कूल भवन बने । पढ़ाई शुरू हुई उस समय का 10 हजार आज 10 लाख से भी ज्यादा है । उनकी उस समय की स्वेच्छा से दान युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई उन्हे नही पढ पाने का दुख था जो अपनी 31 वर्ष की आयु में कोसीर के जिए कुछ किया और उनकी इस सराहनीय योगदान का पुरे अंचल में प्रशंसा हुई।

जो काम गांव के धनाढय परिवार के लोगों की बस की बात नही थी उस काम को एक साधारण व्यक्तिव के किसान के बेटे ने किया । यही नही सत्र 1966 के आस पास पुरे अंचल में सुखा के चपेट में आ गया तब लोगो को भुखे मरने की नौबत आयी तक एक बार फिर समाज के लिए आगे आये और अपने घर में रखे धान को लोगों को दिए बाद में जो लोग लिए थे उपज होने पर दूसरे वर्ष वापस कर दिये । इस तरह समाज के प्रति हमेशा सजग रहे । सत्र 1983 में उनकी तबीयत ठीक नही रहा और तबियत बिगडने से 18 अक्टूबर सन 1987 को उनकी निधन हो गई लगभग 62 वर्ष के थे । दुसरे दिन पुरे गांव में शोक की लहर दौड गई लोगों को बहुत दुख हुआ।

गांव के सभी स्कूलों में दुसरे दिन शोक व्यक्त किया गया और श्रृद्धांजलि देकर छुट्टी कर दी गई। दादा मुन्ना दास के निधन के बाद पुरे परिवार की जिम्मेदारी उनके बडे पुत्र त्रिलोचन जी ने संभाली। आज उनकी योगदान को गांव में बुढे लोग कहते नही थकते हैं ऐसे सामाजिक समरसता के संवाहक युवाओं के प्रेरणा स्त्रोत की पुन जरूरत है। उनकी जीवनी और सामाजिक योगदान पर वर्णन कर पाना मेरे बस की बात नही है फिर भी एक कोशिश है जो मैं उनकी इतिहास को अपने शब्दों में ढालकर बताने की कोशिश कर रहा जो आज भी प्रासंगिक है । आज उनकी 25 फरवरी जन्म दिवस है यह वर्ष उनकी जन्म शताब्दी वर्ष है पर मैं श्रृद्धा सुमन अर्पित करता हूँ जो कोसीर गांव का गौरव और अंचल के युवाओं के प्रेरणा स्त्रोत रहे सादर नमन।

क्लिक के दलदल में फँसा समाज : गालियों से ग्रोथ,शोर से शोहरत

डॉ.सत्यवान सौरभ
भिवानी,हरियाणा

डिजिटल दुनिया कभी ज्ञान, संवाद और रचनात्मकता की प्रयोगशाला मानी जाती थी। यह विश्वास था कि इंटरनेट लोकतंत्र को मज़बूत करेगा,हाशिये पर खड़े लोगों को आवाज़ देगा और असली प्रतिभा को पहचान दिलाएगा। लेकिन आज जब हम स्क्रीन पर उँगली चलाते हैं, तो एक अलग ही सच सामने आता है। यहाँ हुनर से ज़्यादा हंगामा बिकता है,विचार से ज़्यादा विवाद और मेहनत से ज़्यादा मीम। फेशबुक और इंस्टाग्राम जैसे मंचों पर'वायरल'होना सफलता की कसौटी बन चुका है। सवाल यह नहीं कि लोग मशहूर क्यों हो रहे हैं, सवाल यह है कि हम किस तरह की मशहूरी को पुरस्कार बना रहे हैं।

डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का पूरा ढांचा ध्यान के व्यापार पर टिका है। जितनी देर आप स्क्रीन पर टिके रहेंगे,उतना अधिक मुनाफ़ा पैदा होगा। इस गणित में शोर सबसे सस्ता और असरदार हथियार है। ऊँची आवाज़,उग्र भाषा,भड़काऊ हावभाव और अति-नाटकीयता–यही वह मुद्रा है जिसे एल्गोरिद्म सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। जो व्यक्ति ठहराव से,तर्क से और संयम से बात करता है,वह भीड़ में गुम हो जाता है,जबकि तमाशा करने वाला मंच के बीचोंबीच बैठा होता है। यह केवल कंटेंट की समस्या नहीं है,बल्कि प्रोत्साहन की है। जब प्लेटफ़ॉर्म वही दिखाते हैं जो क्लिक दिलाता है,तो रचनाकार भी वही बनाने को मजबूर होता है। इस दौड़ में गुणवत्ता पीछे छूट जाती है और उत्तेजना आगे बढ़ती जाती है। धीरे-धीरे यह एक आदत बन जाती है,और आदत अंततः संस्कृति में बदल जाती है।

कभी हुनर का अर्थ था–अभ्यास,अनुशासन और धैर्य। आज हुनर का मतलब है ट्रेंड पकड़ लेना। कोई सड़क पर नाचकर मशहूर है, कोई गालियाँ देकर 'बोल्ड' कहलाता है, कोई निजी जीवन को सार्वजनिक तमाशा बनाकर 'रियल' होने का दावा करता है। असली प्रश्न यह नहीं कि ये लोग क्यों देखे जा रहे हैं, बल्कि यह है कि समाज किस तरह के आदर्श गढ़ रहा है। यह नया मापदंड युवाओं के मन में एक खतरनाक संदेश बैठा रहा है–कि शॉर्टकट ही सफलता है। अगर आप शांत हैं,तो आप उबाऊ हैं। अगर आप गहरे हैं,तो आप अप्रासंगिक हैं। यह सोच न केवल कला और ज्ञान का अपमान है,बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ज़हरीली है। युवा खुद को लगातार तुलना के आईने में देखने को मजबूर है,जहाँ आत्मसम्मान लाइक्स और व्यूज़ की संख्या से तय होता है।

डर इस बात का है कि आने वाली पीढ़ी किताबें ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि कंटेंट के लिए पढ़े। इतिहास, साहित्य और दर्शन अब सीखने के साधन नहीं, बल्कि विवाद पैदा करने की सामग्री बनते जा रहे हैं। लंबी सोच, संदर्भ और नैतिकता–इन सबको 'बोरिंग' कहकर किनारे किया जा रहा है। जबकि सच यह है कि ज्ञान कभी त्वरित नहीं होता। वह समय मांगता है,धैर्य मांगता है और असहज सवालों से जूझने की ताक़त मांगता है।आज सच बोलने वाले के पास अक्सर सन्नाटा होता है। उसकी बातों में सनसनी नहीं होती,उसके निष्कर्ष तुरंत तालियाँ नहीं बटोरते। दूसरी ओर,तमाशा करने वालों के पास मेला होता है–लाइक्स, शेयर, फॉलोअर्स और ब्रांड डील्स। यह असंतुलन खतरनाक है,क्योंकि समाज शोर से नहीं,संवाद से आगे बढ़ता है। जब संवाद की जगह शोर ले लेता है, तो बहस तमाशा बन जाती है और असहमति दुश्मनी।

युवावर्ग इस पूरे परिदृश्य में सबसे ज़्यादा उलझन में है। एक ओर रोज़गार की अनिश्चितता, दूसरी ओर डिजिटल चमक का झूठा वादा। उसे बताया जा रहा है कि पहचान पाने का सबसे तेज़ रास्ता विवाद है। मेहनत, अध्ययन और धैर्य–ये सब धीमे रास्ते हैं,जबकि दुनिया तुरंत नतीजे चाहती है। इस जल्दबाज़ी की कीमत युवा थकान, अकेलेपन और अंदरूनी खालीपन के रूप में चुका रहा है। अक्सर यह मान लिया जाता है कि प्लेटफ़ॉर्म तटस्थ हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि एल्गोरिद्म नैतिक नहीं होते। वे केवल लक्ष्य देखते हैं,और लक्ष्य है–अधिक समय, अधिक ध्यान। इसलिए वे वही दिखाते हैं जो हमें बाँधे रखे, चाहे वह नफ़रत हो,झूठ हो या खोखला मनोरंजन। ऐसे में जिम्मेदारी केवल प्लेटफ़ॉर्म की नहीं, हमारी भी है। हम जो देखते हैं,वही बढ़ता है। हम जिसे साझा करते हैं,वही फैलता है।

इस सर्कस से बाहर निकलने का रास्ता कोई त्वरित समाधान नहीं है। यह एक धीमी लेकिन ज़रूरी क्रांति है। डिजिटल साक्षरता,गहरी सामग्री को सम्मान, ईमानदार रचनाकारों का समर्थन और अपने देखने-साझा करने के चुनावों के प्रति सजगता – यही वह रास्ता है जिससे दिशा बदली जा सकती है। असहमति को शालीनता के साथ जगह देना और तर्क को ट्रोलिंग पर तरजीह देना भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। डिजिटल संसार का सर्कस बन जाना महज़ एक टिप्पणी नहीं, बल्कि चेतावनी है। सर्कस मनोरंजन देता है, दिशा नहीं। समाज को दिशा चाहिए–ज्ञान से, विवेक से और नैतिक साहस से। अंततः सवाल युवाओं से ही है– आप इस मेले का हिस्सा बनना चाहते हैं, या उस सन्नाटे के गवाह –और वाहक–जो सच के लिए ज़रूरी है?

फैसला आज का है,असर आने वाले कल पर पड़ेगा। शोर आसान है,अर्थ गढ़ना कठिन। लेकिन इतिहास हमेशा उन लोगों को याद रखता है,जिन्होंने कठिन रास्ता चुना।

दौलत की फाइलें,भरोसे के सवाल

प्रियंका सौरभ,
हिसार,हरियाणा

हरियाणा के आईपीएस अधिकारियों की संपत्ति का विवरण सार्वजनिक होने के बाद एक बार फिर प्रशासनिक पारदर्शिता,जवाब देही और नैतिकता पर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। जब जनता के सामने यह तथ्य आते हैं कि कानून-व्यवस्था संभालने वाले कई वरिष्ठ अधिकारियों के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति है–जमीन,प्लॉट,मकान, फार्म हाउस या अन्य निवेश–तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में जिज्ञासा और सवाल दोनों पैदा होते हैं। यह सवाल केवल आंकड़ों का नहीं होता, बल्कि उस भरोसे का होता है जो जनता प्रशासन और शासन पर करती है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारी पद केवल अधिकार का प्रतीक नहीं होता,बल्कि वह जिम्मेदारी और नैतिक आचरण का भी प्रतीक होता है। विशेष रूप से पुलिस और प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी राज्य की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे कानून लागू करते हैं,अपराध पर नियंत्रण रखते हैं और आम नागरिक के अधिकारों की रक्षा करते हैं। ऐसे में जब उनकी आर्थिक स्थिति चर्चा का विषय बनती है, तो जनता यह समझना चाहती है कि यह संपत्ति किस प्रकार अर्जित हुई,क्या यह पूरी तरह वैधानिक है, और क्या इस पर निगरानी की कोई प्रभावी व्यवस्था मौजूद है। संपत्ति का विवरण सार्वजनिक करना निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम है। इससे शासन की पारदर्शिता बढ़ती है और नागरिकों को यह अधिकार मिलता है कि वे सत्ता से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत भी यही है कि सत्ता जनता से छिपी हुई नहीं होनी चाहिए। भारत में कई वर्षों से यह परंपरा रही है कि वरिष्ठ सरकारी अधिकारी अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण सरकार को देते हैं। लेकिन जब यह जानकारी सार्वजनिक होती है,तब उसका महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि तब समाज स्वयं भी उस पर नजर रख सकता है। हालाँकि, केवल आंकड़े सामने आ जाने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता। असली प्रश्न यह है कि क्या इन विवरणों की गंभीरता से जांच भी होती है? क्या यह सुनिश्चित किया जाता है कि घोषित संपत्ति वास्तविकता से मेल खाती है? क्या आय के स्रोत पूरी तरह स्पष्ट हैं? यदि यह प्रक्रिया केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाए तो पारदर्शिता का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। पारदर्शिता तभी सार्थक होती है जब उसके साथ जवाबदेही भी जुड़ी हो।

यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सरकारी सेवाओं में काम करने वाले सभी अधिकारियों को एक ही नजर से देखना उचित नहीं होगा। देश में अनेक ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने ईमानदारी,सादगी और सेवा भावना की मिसाल कायम की है। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने कर्तव्य से समझौता नहीं किया। कई अधिकारी ऐसे भी हैं जो वर्षों तक दूर-दराज के क्षेत्रों में काम करते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। इसलिए किसी भी चर्चा को संतुलित दृष्टि से देखना आवश्यक है। कुछ मामलों के आधार पर पूरे तंत्र को दोषी ठहराना न्यायसंगत नहीं होगा।लेकिन दूसरी ओर यह भी सच है कि पिछले कुछ दशकों में प्रशासनिक तंत्र को लेकर जनता के मन में संदेह बढ़ा है। भ्रष्टाचार के कई मामलों ने लोगों का भरोसा कमजोर किया है। जब आम नागरिक रोजमर्रा के कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाता है, रिश्वत की शिकायतें सुनता है या व्यवस्था की जटिलताओं से जूझता है,तो उसके मन में यह भावना पैदा होती है कि कहीं न कहीं व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। ऐसे माहौल में जब बड़े पैमाने पर संपत्तियों की

खबर सामने आती है,तो संदेह और गहरा हो जाता है। यही कारण है कि संपत्ति के खुलासे को केवल समाचार की तरह देखने के बजाय इसे व्यवस्था को बेहतर बनाने के अवसर के रूप में भी देखा जाना चाहिए। सरकार और संबंधित संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संपत्ति घोषणाओं की नियमित और स्वतंत्र जांच हो। यदि कहीं कोई विसंगति पाई जाती है तो उस पर निष्पक्ष कार्रवाई भी हो। इससे ईमानदार अधिकारियों का मनोबल भी बढ़ेगा और भ्रष्टाचार करने वालों के लिए स्पष्ट संदेश भी जाएगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्रशासनिक तंत्र में नैतिक मूल्यों को मजबूत किया जाए। कानून और नियम जरूरी हैं, लेकिन केवल नियमों के सहारे पूरी व्यवस्था नहीं चलती। अधिकारियों के भीतर सेवा की भावना,जिम्मेदारी का एहसास और सार्वजनिक जीवन की मर्यादा भी उतनी ही आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति उच्च पद पर पहुँचता है तो समाज उससे सामान्य नागरिक की तुलना में अधिक अपेक्षाएँ रखता है। यह अपेक्षा केवल कार्यकुशलता की नहीं बल्कि चरित्र और आचरण की भी होती है।

मीडिया की भूमिका भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों का दायित्व है कि वे तथ्यों को सामने लाएँ,लेकिन साथ ही जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत करें। किसी भी खबर को सनसनी बनाने के बजाय उसके व्यापक सामाजिक और प्रशासनिक संदर्भ को समझना भी जरूरी है। मीडिया यदि संतुलित और तथ्यपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाएगा तो समाज में स्वस्थ बहस का माहौल बनेगा।साथ ही नागरिक समाज की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। लोकतंत्र केवल सरकार या अधिकारियों से नहीं चलता,इसमें जनता की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी होती है। यदि नागरिक जागरूक होंगे, सवाल पूछेंगे और पारदर्शिता की मांग करेंगे तो व्यवस्था स्वाभाविक रूप से अधिक उत्तरदायी बनेगी। सूचना का अधिकार जैसे कानून इसी सोच का परिणाम हैं, जिन्होंने शासन को अधिक खुला बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह भी विचार करने योग्य है कि आज के समय में सरकारी सेवाओं में काम करने वाले अधिकारियों के सामने भी कई चुनौतियाँ हैं।

लगातार बढ़ती अपेक्षाएँ, राजनीतिक दबाव, प्रशासनिक जटिल ताएँ और सामाजिक परिवर्तन–इन सबके बीच काम करना आसान नहीं होता। इसलिए व्यवस्था को केवल आलोचना के दृष्टिकोण से देखने के बजाय सुधार के दृष्टिकोण से देखना अधिक उपयोगी होगा। यदि प्रशासन को मजबूत बनाना है तो उसे पारदर्शिता, प्रशिक्षण, तकनीकी सुधार और नैतिक नेतृत्व–इन सभी पहलुओं पर एक साथ ध्यान देना होगा।

रहस्य का रायता

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा उरतृप्त

शिवपालगंज की धरती पर जब भी कुछ रहस्यमयी होता है,तो समझ लीजिए कि या तो किसी की भैंस चोरी हुई है या फिर चुनाव आने वाले हैं। इस बार मामला जरा हाइब्रिड था। कस्बे के बीचों-बीच बने पुराने डाकबंगले के कमरे नंबर 4 में पिछले तीन दिनों से एक रहस्यमयी परछाई देखी जा रही थी। खि की पर भारी परदे गिरे थे और अंदर से ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे कोई प्रेतात्मा टाइपराइटर पर अपनी आत्मकथा लिख रही हो।

गंजामल जी,जो कस्बे के स्वयंभू जासूस और खाली वक्त में पटवारी थे,ने अपनी चपटी नाक पर चश्मा टिकाते हुए कहा, बेटा, ये मामूली भूत नहीं है। ये प्रजातांत्रिक भूत है। सुन रहे हो अंदर से फाइलें पलटने की आवाज? ये आवो व्यवस्था की अंतरात्मा की है।

देखते ही देखते डाकबंगले के बाहर मेले जैसा माहौल हो गया। बद्री पहलवान अपनी लंगोट कसकर आए थे ताकि अगर भूत कुश्ती के मूड में हो तो दो-दो हाथ हो जाएं। मास्टर साहब ने तर्क दिया कि यह विदेशी जासूस हो सकता है, जो हमारे कस्बे की धूल के नमूनों को चुराकर मंगल ग्रह पर भेजने की फिराक में है। रहस्य की परतें तब और गहरी हो गईं जब स्थानीय दरोगा जी ने अपनी भारी भरकम तोंद संभालते हुए ऐलान किया,अंदर जो भी है, उसके पास राशन कार्ड नहीं है। और जिसके पास राशन कार्ड नहीं, उसे इस देश की हवा में सांस लेने का कोई अधिकार नहीं है। यह घुसपैठिया है! अगले दो घंटों तक योजनाएं बनीं। तय हुआ कि दरवाजा तोड़ा जाए। पूरा गंज उत्सुकता के मारे हिचकिचाहट और रोमांच के बीच झूल रहा था। क्या अंदर कोई आतंकवादी है? क्या कोई बाबा है जो नोट दुगने करने की मशीन चला रहा है? या शायद कोई ऐसा नेता जो भ्रष्टाचार के बोझ से थककर यहाँ एकांतवास में है?

दरोगा जी ने ललकारा–कानून के लंबे हाथ तुम्हारी गर्दन तक पहुँच रहे हैं, बाहर आओ!

अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बस टाइपराइटर की खट-खट तेज हो गई। माहौल में सस्पेंस इतना बे गया कि बद्री पहलवान को पसीना आने लगा। आखिरकार, भारी भरकम लात मारकर दरवाजा तोड़ा गया। धुआं छंटा, और सबकी आँखें फटी की फटी रह गईं।

अंदर न कोई आतंकवादी था, न कोई विदेशी जासूस,और न ही कोई चमत्कारी बाबा।

कमरे के बीचों-बीच एक दुबला-पतला क्लर्क बैठा था,जिसके चारों तरफ फाइलों का पहाड़ था। वह पागलों की तरह टाइपराइटर पर उंगलियां चला रहा था। दरोगा जी ने उसे कॉलर से पकड़ा, कौन हो तुम? यहाँ छिपकर क्या साजिश रच रहे हो?

क्लर्क ने चश्मा ठीक किया, उसकी आँखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कांपती आवो में कहा,साहब,मैं साजिश नहीं रच रहा। मैं सत्य लिख रहा हूँ।

सत्य? कैसा सत्य? मास्टर साहब ने पूछा।

क्लर्क ने मेज पर रखे एक कागज को हवा में लहराया और बोला,साहब,मुझे पिछले दस साल से वेतन नहीं मिला क्योंकि फाइलों में मैं मृत घोषित कर दिया गया था। मैं पिछले तीन दिनों से यहाँ छिपकर खुद के जीवित होने का प्रमाण-पत्र टाइप कर रहा था। लेकिन लिखते-लिखते मुझे अहसास हुआ कि अगर मैं जीवित साबित हो गया,तो मुझे फिर से वही गुलामी करनी पड़ेगी, टैक्स भरने पड़ेंगे और कतारों में खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपनी ही मौत का ऐसा परफेक्ट सरकारी दस्तावेज तैयार किया है कि अब यमराज भी आएँ तो उन्हें अपनी ड्यूटी छोड़कर भागना पड़ेगा।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

-सम्पादक

C M Y K

1.72 लाख करोड़ का बजट पेश

■ आदिवासी अंचलों,महिला सशक्तिकरण और कृषि पर जोर
■ सरगुजा को स्वास्थ्य,पर्यटन और खेल में लाभ की उम्मीद

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,24 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

ओ.पी. चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में वर्ष 2026-27 का 1.72 लाख करोड़ रुपए का आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री चौधरी सरगुजा के प्रभारी मंत्री भी हैं। बजट में दूरस्थ और आदिवासी अंचलों के विकास,महिला सशक्तिकरण,कृषि और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया गया है। हालांकि किसी जिले के लिए अलग से राशि घोषित नहीं की गई है, लेकिन विभिन्न योजनाओं के जरिए सरगुजा संभाग को लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। मेडिकल कॉलेज के विस्तार, अंबिकापुर में नए जिला चिकित्सालय भवन और मैनपाट पर्यटन विकास के लिए प्रावधान किए गए हैं। सरगुजा-बस्तर ओलंपिक के आयोजन का भी उल्लेख किया गया है। कृषक उन्नति योजना-10,000 करोड़ रुपए, कृषि पंपों के लिए बिजली सब्सिडी- 5,500 करोड़ रुपए,प्रधानमंत्री फसल बीमा-820 करोड़ रुपए,पीएम जनमन योजना-720 करोड़ रुपए,धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान-200 करोड़ रुपए,500 नए आंगनबाड़ी केंद्र,250 महतारी सदन निर्माण - 75 करोड़ रुपए,रानी दुर्गावती योजना के तहत 18 वर्ष पूर्ण करने पर पात्र बालिकाओं को 1.50 लाख रुपए सहायता,लोक निर्माण विभाग-9,450 करोड़ रुपए,जल संसाधन-3,500 करोड़ रुपए, नगरीय विकास-2,150 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

भाजपा ने सराहा

लक्ष्मी राजवाड़े,कैबिनेट मंत्री,छत्तीसगढ़ शासन ने यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि प्रदेश की माताओं,बहनों और बेटियों के आत्मविश्वास को सशक्त करने का ठोस खाका है। सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा,स्वास्थ्य,पोषण,सुरक्षा और आर्थिक स्वावलंबन को नीति के केंद्र में रखकर समावेशी विकास का स्पष्ट संदेश दिया है। 250 महतारी सदनों के निर्माण के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 500 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण होगा। रानी दुर्गावती योजना में 18 वर्ष पूर्ण करने पर पात्र बालिकाओं को 1.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

बजट प्रतिक्रिया

राजेश अग्रवाल (केबिनेट मंत्री)

कृषक उन्नति योजना 10,000 करोड़, कृषि पंपों हेतु 5,500 करोड़ बिजली सब्सिडी, प्रधानमंत्री फसल बीमा 820 करोड़ ये प्रावधान किसानों की लागत घटाकर आय बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम हैं। पूंजीगत निवेश से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

प्रबोध मिंज (विधायक)

पीएम जनमन योजना 720 करोड़, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान 200 करोड़, 25 प्री-मैट्रिक/पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास हेतु 75 करोड़ जनजातीय शिक्षा व सामाजिक सशक्तिकरण को नई मजबूती देंगे।

रामकुमार टोप्पो (विधायक)

सरगुजा-बस्तर क्षेत्र के लिए अतिरिक्त पोषण सहायता 15 करोड़, हवाई सेवाओं के विस्तार हेतु 80 करोड़ अधोसंरचना प्रावधान, मेडिकल कॉलेज संचालन हेतु 50 करोड़ क्षेत्रीय संतुलित विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

भारत सिंह सिसोदिया (जिलाध्यक्ष)

लोक निर्माण विभाग हेतु 9,450 करोड़, जल संसाधन 3,500 करोड़, द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना 200 करोड़ बुनियादी ढांचे को मजबूत कर प्रत्यक्ष रोजगार सृजन करेंगे साथ ही अंबिकापुर में नये ज़िला चिकित्सालय भवन की स्वीकृति संभाग के मरीजों के लिए संजीवनी के रूप में कार्य करेंगे।

मंजूषा भगत (महापौर)

नगरीय विकास 2,150 करोड़, नगरीय अधोसंरचना 750 करोड़, मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना 200 करोड़ शहरी सुविधाओं के आधुनिकीकरण का रोडमैप है।

अरुणा सिंह (भाजपा नेत्री)

रानी दुर्गावती योजना 15 करोड़, महिला पंजीयन शुल्क में 50% छूट, 750 नए आंगनबाड़ी भवन महिलाओं की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

विश्व विजय सिंह तोमर (अध्यक्ष,युवा आयोग)

CG ACE 33 करोड़,मेगा परीक्षा केंद्र 25 करोड़,स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट स्कूल योजना 100 करोड़,स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन युवाओं के कौशल और रोजगार क्षमता में गुणात्मक वृद्धि करेंगे।

अम्बिकेश केशरी (भाजपा नेता)

औद्योगिक पूंजी निवेश सब्सिडी 750 करोड़,23 नए औद्योगिक पार्क हेतु 250 करोड़,लैंड बैंक विकास 200 करोड़ उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था को गति देंगे।

विनोद हर्ष (जिला महामंत्री)

महिला एवं बाल विकास 11,000 करोड़,महतारी वंदन योजना 8,200 करोड़,आंगनबाड़ी सशक्तिकरण 2,320 करोड़ महिला सशक्तिकरण को आर्थिक आधार प्रदान करते हैं।

रुपेश दुबे (जिला मीडिया प्रभारी)

राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,79,244 (10% वृद्धि अनुमान),कुल प्राप्तियां 1,72,000 करोड़, तथा अगले 5 वर्षों तक प्रत्येक मुख्यमंत्री मिशन हेतु 100-100 करोड़ वार्षिक प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि बजट केवल घोषणा नहीं बल्कि दीर्घकालिक क्रियान्वयन का संकल्प है। सरगुजा सहित पूरे प्रदेश में इसका व्यापक सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा।

संतोष दास (प्रवक्ता)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 820 करोड़ और सरगुजा सहित पूरे छत्तीसगढ़ के गन्ना किसानो के बोनस हेतु 60 करोड़ का प्रावधान किसानो की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा

धनंजय मिश्रा (सह संवाद प्रमुख)

विकसित भारत जी रामजी योजना के तहत 4000 करोड़ का बड़ा प्रावधान किया गया है इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 125 दिवस का सुनिश्चित रोजगार दिया जाएगा साथ ही आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण एवं जन सुविधा भी विकसित की जाएगी द्य इस प्रकार यह बजट किसान, युवा, महिला, आदिवासी एवं शहरी ग्रामीण सभी वर्गों के लिए विकास का मजबूत आधार है और विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के लक्ष्य की दिशा में निर्णायक कदम है।

कांग्रेस की प्रतिक्रिया

पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में रखे गये बजट के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया है ऐसे में राज्य सरकार का 1.72 लाख का बजट प्रोविजन बेमानी है। राज्य सरकार का राजस्व व्यय पिछले बजट की राशि 1.38 लाख की तुलना में बढ़कर 1.45 लाख करोड़ हो गया है उसकी तुलना में पूंजीगत व्यय 26341 करोड़ रुपए से बढ़कर 26500 करोड़ हुआ है जो बेहद निराशाजनक है। एक ओर प्रदेश की सरकार डबल इंजन के नाम पर अधोसंरचना विस्तार की बड़ी बडी बात कर रही है वहीं प्रावधान ऊंट के मुंह में जीरा होगा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने बजट 2026 के लिए संकल्प रूपी जुमले का उपयोग करते हुए सरगुजा संभाग के ज्ञान(गरीब,युवा,अन्नदाता, नारी) के साथ छल किया है। इस बजट में सरगुजा के उस ज्ञान को कुछ भी नया नहीं मिला जिसने भाजपा की झोली में 14 सीटें डाली थी। बजट में सरगुजा को उद्योग, रोजगार-स्वरोजगार, सिंचाई, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मनरेगा के स्थान पर लायी गयी जी राम जी योजना के लिए बजट में मात्र 4000 करोड़ का योगदान है। यह केंद्र के अंशदान को मिलाकर है। प्रदेश में 85 लाख मजदूरों को 125 दिन के काम का भुगतान 26 हजार करोड़ होगा। तो क्या जी राम जी योजना प्रदेश की श्रमशक्ति से छलावा है। जी राम जी मे पहले केंद्र का बजट प्रावधान फिर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का बजट प्रावधान कांग्रेस की इस आशंका को मजबूत करता है कि मनरेगा को समाप्त कर लायी गई जी राम जी योजना देश की श्रम शक्ति के साथ भाजपा का बहुत बड़ा धोखा है। महतारी वंदन के मद में मात्र 8200 करोड़ का प्रावधान है,जबकि विगत वर्ष इसपर 14000 करोड़ खर्च हुए। क्या प्रदेश की सरकार ने महतारी वंदन योजना से लाखों महिलाओं को बाहर करने की किसी छिपी योजना पर कार्य कर रही है,इसे सरकार अवश्य बताये।

ललन प्रताप सिंह (पूर्व जिलाध्यक्ष)

राजस्व व्यय 1,45,000 करोड़, पूंजीगत व्यय 26,500 करोड़ तथा सतुलित 2.87% राजकोषीय घाटाविकास और वित्तीय अनुशासन का आदर्श संतुलन है।

अनिल सिंह मेजर (भाजपा नेता)

गृह विभाग 8,380 करोड़,साइबर तहसील स्थापना, प्रशासनिक आवास निर्माण सुरक्षा एवं सुशासन को और मजबूत करेंगे।

महापौर बोलीं-दूषित पानी की सूचना नहीं दी गई,सफाई व्यवस्था पर उठाए सवाल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,24 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 48 और घुटरापारा में पीलिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पिछले चार दिनों में यहां 56 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार बीमारी की वजह दूषित पानी की सप्लाई है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित वार्डों में कैंप लगाकर जांच और उपचार शुरू कर दिया है। मंगलवार को महापौर मंजूषा भगत ने प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि दूषित पानी की सप्लाई की जानकारी न तो उन्हें दी गई और न ही निगम आयुक्त को। उन्होंने वार्ड की सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए कहा कि नालियां गंदगी से अटी पड़ी हैं और लंबे समय से सफाई नहीं कराई गई है। महापौर ने कहा कि उन्हें करीब 10 दिन पहले ही स्थिति की जानकारी मिली। जबकि 3-4 महीने पहले भी यहां पीलिया का एक मरीज सामने आया था, जिसकी सूचना नगर निगम या जल विभाग को नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते सूचना मिलती तो पानी की जांच और सफाई कराई जा सकती थी। उन्होंने यह भी कहा कि निगम क्षेत्र के हजारों लोग यही पानी पी रहे हैं, लेकिन संक्रमण केवल एक ही वार्ड में अधिक मिल रहा है। यह जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि अचानक बड़ी संख्या में मरीज सामने आना संदेह पैदा करता है।

सभी को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी

महापौर ने कहा कि शहर को साफ-सुथरा रखना सभी की जिम्मेदारी है। वार्ड में चारों ओर गंदगी देखकर लग रहा है कि वर्षों से नियमित सफाई नहीं हुई है। यदि पहले सूचना दी जाती तो हालात इतने नहीं बिगड़ते। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रभावित क्षेत्र में सफाई, पानी की जांच और स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी लगातार की जाएगी। कुछ पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर हालचाल भी जाना गया। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप लगाकर लोगों की जांच कर रही है और लोगों से साफ पानी पीने तथा सावधानी बरतने की अपील की गई है।

राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी हैं लैंड जेहाद के शिकार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,24 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

जमीन की हवस ने राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पंडों समाज को भी नहीं छोड़ा, इस अति विशेष जनजाति के लोग अपने हीं गाँव में निर्वासित जीने के लिए बाध्य हैं। पूरा प्रकरण लखनपुर विकासखंड के ग्राम राजाकटेल, चोड़ेया एवं माजा का है। आज भाजपा सरगुजा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया अपने भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ लखनपुर क्षेत्र के प्रवास पर थे तो ग्राम राजाकटेल के पंडों समाज के सैकड़ों लोगों ने अपनी व्यथा को श्री सिसोदिया के समक्ष प्रस्तुत किया। पंडों समाज के लोगों ने बताया कि हमारी पुरखों की जमीन धमकाकर एवं छलपूर्वक बाहरी लोगों ने हड़प ली है,और जबरदस्ती क़ब्ज़ा कर लिया है, जो भूमि हमारे जीविकोपार्जन का एक मात्र माध्यम था और जो हमारे पूर्वजों की एकमात्र धरोहर थी आज उस पर पंडों समाज का नहीं बल्कि कुर्बान,खुर्शीद,शफ़ीक़,सरफुद्दीन, रज़्ज़ाक़, रफ़ीक़ और निसार जैसे सैकड़ों बाहरी लोगों का मुख्यमार्ग से लेकर भीतर खेती बाड़ी तक क़ब्ज़ा है। आश्चर्य का विषय है कि वर्षों से इस तरह का गतिविधियों से भयभीत पंडों समाज अपनी व्यथा को अभिव्यक्त नहीं कर सका,जबकि संविधान में उल्लेखित है कि आदिवासी वर्ग की भूमि कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति क्रय नहीं कर सकता , उसके उपरांत भी विशेष समुदाय के लोगों ने किस भाव एवं षड्यंत्र के तहत एक पूरे गाँव के ग़रीब पंडों समाज के लोगों के साथ छल करते

हुए 70% से अधिक भू भाग पर क़ब्ज़ा कर लिया है,और कुछ लोगों ने न जाने किस भू अधिनियम के तहत आदिवासी जमीन की रजिस्ट्री भी करा ली है,साथ हीं विशेष समुदाय के नाम पर वनभूमि पट्टा बन गया है और उनके नाम पर भूमि का नामांतरण भी हो चुका है। पंडों समाज के लोगो से संवाद करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया के कहा कि विगत दिनों समाचार के माध्यम से ज्ञात हुआ कि पंडों समाज के लोगों द्वारा कलेक्टर सरगुजा से मिल कर इस बात की शिकायत की गई है । उन्होंने कहा कि यह गंभीर विषय है जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों जो कि अति विशेष जनजाति आदिवासी समाज से आते हैं उनकी पैतृक भूमि कैसे अन्य लोगों के नाम पर चला गया और कैसे बाहरी लोगों का इस पर क़ब्ज़ा हो गया,ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि बकरियां खरीदने के लिए आए हुए लोगों द्वारा आश्रय के लिए झोपड़ी बनाने के लिए माँगी गई जमीन धीरे धीरे पक्की भवनों में तब्दील हो गई,और आज राजाकटेल के पंडों जनजाति संख्या और जमीन बहुत कम हो गई है ।

भाजपा जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने माजा ग्राम में पण्डो समाज की भूमि समस्या पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया

-संवाददाता-
लखनपुर,24 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

मंगलवार को भाजपा जिला अध्यक्ष आदरणीय भारत सिंह सिसोदिया एवं भाजपा प्रतिनिधिमंडल का मण्डल प्रवास कार्यक्रम भाजपा मण्डल कुन्नी के ग्राम पंचायत मांजा में हुआ, जिसमें पण्डो समाज के सैकड़ों लोगों उपस्थित होकर जिला अध्यक्ष एवं सभी अतिथियों का स्वागत किए तथा सभी ग्रामवासियों ने अपनी समस्याओं को प्रतिनिधिमंडल के समक्ष रखा की किस प्रकार से एक समुदाय विशेष के लोगों ने पण्डो समाज के व्यक्तियों के पट्टे की जमीन पर बलपूर्वक घर बना कर एवं खेती बड़ी हेतु कब्जा कर लिया है समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुनते हुए तुरंत जिलाध्यक्ष के संबंधित अधिकारियों को मौके में बुलाकर सभी को उचित न्याय दिलाने हेतु आग्रह किया एवं भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर हर सम्भव मदद का आश्वासन भी दिया उक्त कार्यक्रम में जिला महामंत्री विनोद हर्ष जिला उपाध्यक्ष दिनेश साहू,चंद्रिका प्रसाद यादव,किसान मोर्चा उपाध्यक्ष अजीत सिंह , दिनेश गुप्ता जन्मेजय मिश्रा,निलेश सिंह मण्डल अध्यक्ष रवि महंत, दिनेश बारी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष निशांत सिंह,विजय व्यापारी, सुरेन्द्र साहू सरपंच खेमराज सिंह,बीडीसी सुदर्शन सिंह एवं क्षेत्र के सभी भाजपा कार्यकर्ता एवं भारी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

अंबिकापुर में दूषित जल से पीलिया का खतरा स्वास्थ्य शिविर लगाने की मांग तेज.....

-संवाददाता-
अंबिकापुर,24 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

नगर पालिक निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में दूषित पेयजल आपूर्ति की शिकायतों के बीच पीलिया (जॉन्डिस) के बढ़ते मामलों ने शहर की चिंता बढ़ा दी है, स्थानीय नागरिकों के अनुसार बीते कुछ दिनों से कई परिवारों में उल्टी, कमजोरी, पीलापन और बुखार जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं,जिनकी जांच में पीलिया के मामले सामने आ रहे हैं। स्थिति को गंभीर बताते हुए राज्य अधिवक्ता परिषद छत्तीसगढ़ के सदस्य प्रवीण गुप्ता ने आयुक्त,नगर पालिक निगम अंबिकापुर को लिखित आवेदन सौंपकर आपातकालीन कदम उठाने की मांग की है। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि जल आपूर्ति में संक्रमण के कारण नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में है और यदि तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो स्थिति और भयावह हो सकती है।

स्वास्थ्य शिविर की मांग-आवेदन में प्रभावित वार्डों में विशेष स्वास्थ्य शिविर (हेल्थ कैंप) लगाने की मांग की गई है,ताकि संभावित और संक्रमित मरीजों की समय रहते जांच एवं उपचार हो सके। मांग है कि चिकित्सा दल को मौके पर भेजकर घर-घर सर्वे कराया जाए और गंभीर मरीजों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया जाए।

निगरानी टीम और जल गुणवत्ता जांच आवेदन में यह भी सुझाव दिया गया है कि निगम स्तर पर एक विशेष निगरानी टीम गठित की जाए, जो स्वयं वार्डों में जाकर जल गुणवत्ता की जांच करे। पाइपलाइनों में रिसाव, सीवेज मिलावट या अन्य तकनीकी खामियों की पहचान कर उन्हें तत्काल दुरुस्त किया जाए, विशेषज्ञों का मानना है कि पीलिया प्रायः दूषित पानी के सेवन से फैलता है, इसलिए जल स्रोतों की स्वच्छता और क्लोरीनेशन की नियमित निगरानी अत्यंत आवश्यक है।

वैकल्पिक स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था-प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी रूप से टैंकरों के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है। नागरिकों का कहना है कि जब तक पाइपलाइन और स्रोत पूरी तरह सुरक्षित घोषित न हों, तब तक वैकल्पिक व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए।

प्रशासन की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित

फिलहाल नगर निगम प्रशासन की ओर से आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों का कहना है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, शहरवासियों की मांग है कि मामले को हल्के में न लिया जाए और पारदर्शी तरीके से जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, जनस्वास्थ्य से जुड़ा यह मुद्दा अब शहर में चर्चा का प्रमुख विषय बन चुका है, अब निगाहें नगर निगम प्रशासन पर हैं—क्या तत्काल स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे और जल आपूर्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी, या फिर नागरिकों को इंतजार करना पड़ेगा?

फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी से जमीन सौदा,आरोपी गिरफ्तार

दो लाख रुपए अग्रिम लेकर करता रहा टालमटोल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,24 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा पुलिस की कोतवाली पुलिस ने जमीन विक्रय के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने फर्जी अधिकार पत्र दिखाकर पीड़ित से दो लाख रुपए अग्रिम ले लिए थे। पुलिस के अनुसार चर्च रोड केदारपुर निवासी प्रीतपाल सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि ग्राम मोरभंज, तहसील लटोरी जिला सूरजपुर स्थित भूमि का 35 लाख रुपए में सौदा किया गया था। सौदे के तहत दो लाख रुपए बैंक चेक के माध्यम से आरोपी को दिए गए थे। बाद में जांच में पता चला कि भूमि के वास्तविक स्वामी ने आरोपी को कोई वैध अधिकार पत्र नहीं दिया था। जांच के दौरान आरोपी के कब्जे से मुख्तारनामा आम (जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी) जब्त किया गया।

न्यायालय तहसीलदार अंबिकापुर के न्यायालय में मामला क्रमांकः. 202602020700204

विषयः-अ-6 मामले की श्रेणीः- राजस्व सनः-2025-26

सपना प.ह.न. 00028 [563/11 (0.0520हे0)]
पक्षकारों का विवरण -
आवेदक पक्षकार - अमरनाथ सिंह, अनावेदक पक्षकार - रामप्रताप,

ईश्तहार

आवेदक अमरनाथ सिंह आ0हरिनाथ सिंह निवासी ग्राम सपना तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा ग्राम सपना स्थित भूमि खसरा नंबर 563/11 रकबा 0.052 हे0 भूमि के राजस्व अभिलेखो में पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 29-08-2024 के माध्यम से नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पेश किया गया है। उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 11.03.2026 के पूर्व न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 17/02/2026 को जारी किया जाता है।

सील

उमेश्वर सिंह बाज
तहसीलदार,अंबिकापुर

26 साल बाद स्काउट्स को मिला अपना भवन...सेवा और समर्पण का नया केंद्र बनेगा जिला कार्यालय

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,24 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

भारत स्काउट्स एवं गाइड्स सरगुजा जिला संघ को 26 वर्षों के इंतजार के बाद अपना स्वतंत्र और सुसज्जित जिला कार्यालय भवन मिल गया। 23 फरवरी 2026 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में नवीन कार्यालय व हॉल का लोकार्पण जिला मुख्य आयुक्त तजिंदर सिंह बग्गा और जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार झा की उपस्थिति में हुआ। जिला मुख्य आयुक्त बग्गा ने कहा कि यह भवन सेवा,अनुशासन और राष्ट्र निर्माण की भावना को मजबूती देगा। उन्होंने इसे सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया। डॉ. झा ने स्काउटिंग को विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण की प्रभावी पाठशाला बताते हुए निरंतर प्रशासनिक सहयोग का आश्वासन दिया। जिला संगठन आयुक्त योगेश विश्वकर्मा के प्रयासों की सराहना करते हुए वक्ताओं ने कहा कि उनके नेतृत्व और सतत प्रयासों से यह उपलब्धि संभव हो सकी। उन्होंने राज्यपाल पुरस्कार में अधिक सहभागिता और शीघ्र प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने की घोषणा की। कार्यक्रम में सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई तथा जिला व ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों,स्काउटर-गाइडर,सीनियर रोवर्स व रेंजर्स को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

'कुर्सी पहले, मंजूरी बाद में!' कोरिया साहू समाज में अध्यक्ष पद की 'घोषणा लीला' पर सवाल

मुहर के बिना ही कुर्सी पर कब्जा? कोरिया साहू समाज में अध्यक्ष पद पर संग्राम

पहले घोषणा,फिर मान्यता!' जिला साहू संघ में स्वयंभू अध्यक्ष का विवाद

प्रदेश की सहमति अधूरी,फिर भी अध्यक्ष पूरी तैयारी में!

कुर्सी की जल्दी या संगठन की मर्यादा?' साहू समाज में बढ़ता टकराव

लेटर पैड से अध्यक्ष बनेंगे?' कोरिया साहू संघ में वैधता पर सवाल

घोषणा बनाम मान्यता'-जिला साहू संघ में दो धाराओं की आहट

सहमति के बिना विस्तार!' क्या साहू समाज में बढ़ रही है गुटबाजी?

घटती-घटना फॉलोअप

कोरिया,24 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

पहले भी इस मुद्दे पर कई खबरें प्रकाशित हो चुकी हैं, लेकिन मामला शांत होने के बजाय और उलझता जा रहा है, जिला साहू संघ कोरिया में अध्यक्ष पद को लेकर चल रहा विवाद अब खुलकर 'घोषणा बनाम मान्यता' की लड़ाई बनता नजर आ रहा है। समाज के एक वर्ग का आरोप है कि जब प्रदेश साहू संघ रायपुर से अब तक सैद्धांतिक और लिखित सहमति नहीं मिली, तो आखिर किस अधिकार से जगदीश साहू स्वयं को जिला अध्यक्ष घोषित कर कार्यकारिणी विस्तार पर उतारू हैं? क्या यह संगठनात्मक प्रक्रिया है या 'पहले कुर्सी पकड़ो, बाद में कागज देखेंगे' वाली रणनीति?

स्वयंभू अध्यक्ष' का नया अध्याय?

समाज के वरिष्ठजनों का कहना है कि जब प्रदेश स्तर से नाम पर मुहर ही नहीं लगी, तब जिला स्तर पर आदेश जारी करना, बैठकें बुलाना और पद बांटना क्या दर्शाता है? कुछ लोगों ने तंज कसते हुए कहा – 'लगता है अब अध्यक्ष बनने के लिए चुनाव या सहमति की नहीं,आत्मविश्वास की जरूरत है।' आरोप है कि बिना वैधानिक प्रक्रिया पूरी किए जारी किए गए आदेश समाज में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं,जिला साहू संघ कोरिया के भीतर यह सवाल जोर पकड़ रहा है कि क्या संगठन अब दो समानांतर धाराओं में बंटने की ओर बढ़ रहा है?

लेटर पैड भी बना चर्चा का विषय

विवाद सिर्फ पद की घोषणा तक सीमित नहीं है, कथित रूप से जारी लेटर पैड और आदेशों की प्रतिलिपि प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष को नहीं भेजे जाने का भी आरोप है, समाज के एक पदाधिकारी ने व्यंग्य में कहा – 'अगर पत्र की कॉपी प्रदेश तक ही नहीं पहुँची, तो यह आदेश समाज के लिए है या सिर्फ समर्थकों के लिए?' यह सवाल अब खुलकर पूछा जा रहा है कि क्या यह सब संगठन को मजबूत करने के लिए है, या फिर कुछ चुनिंदा लोगों के साथ मिलकर 'अपनी अध्यक्षीय पारी' खेलने की कोशिश?

समाज जोड़ने की कोशिश या तोड़ने की?

समाज के कई लोगों का मानना है कि जब प्रदेश संगठन की सहमति ही लंबित है, तब जल्दबाजी में कार्यकारिणी विस्तार करना संगठनात्मक अनुशासन पर प्रश्न खड़े करता है, व्यंग्यात्मक चर्चा में यह भी कहा जा रहा है कि – 'प्रदेश की मुहर बाद में लगे या न लगे, लेकिन बधाई संदेश पहले ही तैयार हैं।' समाज के वरिष्ठजनों ने साफ कहा है कि जब तक प्रदेश स्तर से स्पष्ट लिखित सहमति नहीं मिलती, तब तक किसी भी प्रकार की अध्यक्षीय घोषणा को वैध नहीं माना जाएगा।

बड़ा सवालः महत्वाकांक्षा या संगठन? अब सवाल यह उठ रहा है कि यह पूरी कवायद आखिर किसलिए?

क्या यह व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का परिणाम है? या संगठन के भीतर किसी गुटबाजी की नई पटकथा लिखी जा रही है? पूर्व में प्रकाशित खबरों के बाद भी यदि स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है, तो यह संकेत है कि मामला सिर्फ पद का नहीं, बल्कि प्रक्रिया और पारदर्शिता का भी है, अब निगाहें प्रदेश नेतृत्व पर टिकी हैं, क्या प्रदेश साहू संघ रायपुर इस पूरे विवाद पर आधिकारिक स्पष्टता जारी करेगा? या फिर जिला स्तर पर 'घोषणा बनाम मान्यता' का यह खेल आगे भी चलता रहेगा? फिलहाल समाज के भीतर चर्चा यही है – 'अध्यक्ष बनने की जल्दी ज्यादा है या संगठन की मर्यादा की चिंता?'

अंबिकापुर-जबलपुर ट्रेन हादसा...24 वर्षीय युवक के दोनों पैर कटे,साहसी युवती की तत्परता से बची जान

दिल दहला देने वाला हादसाः ट्रेन की चपेट में आया युवक,साहस की मिसाल बनी युवती

- अंबिकापुर-जबलपुर ट्रेन हादसाः युवक के कटे दोनों पैर,युवती बनी फरिश्ता
- पटरी पर छटपटाता रहा युवक, युवती की हिम्मत ने बचाई जान
- दोनों पैर गंवाए,पर जिंदा है उम्मीद–एक युवती की सूझबूझ से बची जान

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर,24 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

शनिवार की रात सूरजपुर जिले में हुई एक भयावह घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। अंबिकापुर-जबलपुर पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से 24 वर्षीय युवक के दोनों पैर जांघ के ऊपर से कट गए। युवक रेलवे ट्रैक पर गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा मिला। समय पर एक युवती की हिम्मत और सूझबूझ के कारण उसे अस्पताल पहुंचाया जा सका,जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

दोस्तों के साथ निकला था,देर रात मिली सूचना

जानकारी के अनुसार,गोपालपुर निवासी मयंक तिवारी (पिता मनोज नाथ तिवारी), उम्र 24 वर्ष, शनिवार शाम को अपने दोस्तों के साथ घर से घूमने निकला था, देर रात तक घर वापस नहीं लौटने पर परिजन चिंतित थे, इसी बीच रात करीब 10:30 बजे परिजनों को मोबाइल के माध्यम से सूचना मिली कि सूरजपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 500 मीटर की दूरी पर अंबिकापुर-जबलपुर ट्रेन की चपेट में आने से मयंक गंभीर रूप से घायल हो गया है, सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल की ओर दौड़े, रेलवे फाटक के पास ट्रेन की रफ्तार धीमी थी,चालक को हादसे की भनक लगते ही ट्रेन रोक दी गई। नीचे उतरकर यात्रियों ने देखा कि युवक पटरी पर छटपटा रहा है, उसके दोनों पैर घुटनों के ऊपर से कट चुके थे और खून बह रहा था।

भीड़ खड़ी रही,युवती ने संभाली कमान

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना का दृश्य इतना भयावह था कि कई यात्री नीचे उतरकर दूर से देख रहे थे,लेकिन कोई सीधे मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, तभी कटनी से अंबिकापुर आ रही एक युवती ने असाधारण साहस दिखाया, उसने मोबाइल की टॉर्च जलाकर ट्रेन के नीचे जाकर युवक की स्थिति देखी, तुरंत अपने स्टॉल (दुपट्टे) को फाड़कर कटे हिस्सों पर कसकर बांधा,ताकि रक्तस्राव रोका जा सके,इसके बाद आसपास मौजूद लोगों की मदद से युवक को सावधानीपूर्वक बाहर निकाला गया,बताया जा रहा है कि गंभीर अवस्था में भी युवक होश में था और बात कर पा रहा था, युवती ने उसका मोबाइल लेकर पासवर्ड पूछा और उसके परिजनों को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी। इस बीच स्थानीय लोगों ने एंबुलेंस की व्यवस्था की।

मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी

गंभीर रूप से घायल मयंक तिवारी को तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया,डॉक्टरों की टीम ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत को अत्यंत गंभीर बताया है,अत्यधिक रक्तस्राव के कारण स्थिति नाजुक बनी हुई है, चिकित्सक लगातार निगरानी कर रहे हैं।

हादसा, आत्मघात या साजिश?

घटना के बाद इलाके में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं,कुछ लोगों का दावा है कि युवक के पैर बांधकर उसे पटरी पर लिटाया गया था,वहीं दूसरी ओर यह भी चर्चा है कि युवक अपने दोस्तों के साथ था और संभवतः शराब सेवन के बाद विवाद की स्थिति बनी,हालांकि पुलिस ने अभी किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया है,मामले की जांच शुरू कर दी गई है,सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और युवक के साथ रहे लोगों से पूछताछ की जा रही है,ताकि यह स्पष्ट हो सके कि मामला दुर्घटना है,आत्मघाती कदम है या किसी आपराधिक साजिश का हिस्सा।

रेलवे सुरक्षा पर भी सवाल

यह घटना रेलवे ट्रैक के पास सुरक्षा व्यवस्था और जागरूकता को लेकर भी सवाल खड़े करती है, देर रात रेलवे फाटक के पास युवक का ट्रैक पर पहुंचना और इस प्रकार ट्रेन की चपेट में आना कई संभावनाओं की ओर इशारा करता है।

साहसी युवती

बहादुरी की मिसाल बनी युवती

इस दर्दनाक घटना के बीच जिस युवती ने साहस दिखाया,उसकी सर्वत्र सराहना हो रही है, यदि वह समय पर रक्तस्राव रोकने का प्रयास न करती,तो स्थिति और भयावह हो सकती थी, स्थानीय लोग उसे 'साहस की मिसाल' बता रहे हैं, एक ओर जहां यह घटना परिवार और क्षेत्र के लिए गहरा आघात है, वहीं दूसरी ओर यह मानवता और साहस की एक प्रेरक कहानी भी बन गई है, अब सबकी नजर पुलिस जांच और युवक की स्वास्थ्य स्थिति पर टिकी है।

विकास पुरुष का टूटा बोर्ड बना सियासी मुद्दा,एक साल बाद लौटा सम्मान

- मंच पर सम्मान,जमीन पर उपेक्षा? बैकुंठपुर में उठा बड़ा सवाल
- टूटा नामपट्ट और राजनीतिः तीरथ गुप्ता के सम्मान पर घमासान
- एक साल अंधेरे में रहा सम्मान,अब जागी जिम्मेदारी
- सजावट में चमका शहर,पर 'विकास पुरुष' का बोर्ड भूला प्रशासन
- बोर्ड जुड़ा तो खुली राजनीति की परतें
- शब्दों में सम्मान या कर्म में? बैकुंठपुर में नई बहस
- तीरथ गुप्ता स्मृति कॉम्प्लेक्स का टूटा बोर्ड बना जनचर्चा का केंद्र
- सम्मान की मरम्मतः उपाध्यक्ष की पहल से फिर जला स्वाभिमान

-संवाददाता-

बैकुंठपुर,24 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

शहर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय तीरथ गुप्ता को बैकुंठपुर की जनता आज भी 'विकास पुरुष' के रूप में याद करती है,उनके कार्यकाल में हुए निर्माण कार्यों और शहरी विकास की पहल ने उन्हें एक अलग पहचान दी,इसी योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से नगर परिषद ने उनके नाम पर एक कॉम्प्लेक्स का नामकरण किया था और वहां उनके नाम का बोर्ड भी स्थापित किया गया था। लेकिन समय के साथ वही बोर्ड उपेक्षा का शिकार हो गया, पिछले लगभग एक वर्ष से बोर्ड टूटी अवस्था में पड़ा था,शहर के व्यस्त क्षेत्र में स्थित इस कॉम्प्लेक्स का नामपट्ट खंडित और जर्जर हालत में होने के बावजूद उसकी मरम्मत की ओर ध्यान नहीं दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह केवल एक बोर्ड नहीं,बल्कि शहर की स्मृतियों और सम्मान का प्रतीक है,एक टूटे हुए बोर्ड ने बैकुंठपुर में सम्मान,जिम्मेदारी और राजनीति–तीनों को एक साथ चर्चा में ला दिया है। यह घटनाक्रम याद दिलाता है कि स्मृति चिह्न केवल नामकरण से जीवित नहीं रहते, बल्कि उनकी देखरेख और संवेदनशीलता से उनका सम्मान कायम रहता है, अब शहर में सवाल यही है–क्या यह पहल आगे भी इसी तरह जिम्मेदारी निभाने का संकेत बनेगी, या फिर यह मुद्दा भी कुछ दिनों में राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रह जाएगा?

सजावट दिखी,सम्मान नहीं?

राजनीतिक चर्चा तब तेज हो गई जब हाल ही में प्रदेश नेतृत्व का बैकुंठपुर दौरा हुआ, शहर में चौक-चौराहों की सजावट की गई, सड़कों की साफ-सफाई और रंग-रोगन पर विशेष ध्यान दिया गया। परंतु स्व. तीरथ गुप्ता जी के नाम का टूटा बोर्ड जस का तस बना रहा, आलोचकों का आरोप है कि मंचों से 'विकास पुरुष' कहकर तालियां बटोरी जाती हैं,लेकिन उनके नाम से जुड़े स्थायी प्रतीकों के संरक्षण की जिम्मेदारी नहीं निभाई जाती, यह सवाल भी उठ रहा है कि यदि शहर के एक प्रमुख कॉम्प्लेक्स का नामपट्ट एक साल तक टूटा पड़ा रहे, तो यह प्रशासनिक संवेदनशीलता पर प्रश्नचिन्ह नहीं तो और क्या है?

पहल किसने की?-बैकुण्ठपुर नगर पालिका उपाध्यक्ष आशीष यादव और उनके पार्षदों ने स्वयं आगे आकर इस बोर्ड को पुनः बनवाने और स्थापित करने का निर्णय लिया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और मरम्मत कार्य पूरा करवाया, उनका कहना है कि यह केवल एक बोर्ड की मरम्मत नहीं,बल्कि स्वर्गीय तीरथ गुप्ता जी के सम्मान की पुनर्स्थापना है, उनके समर्थकों के अनुसार,'सम्मान भाषणों से नहीं,जिम्मेदारी निभाने से मिलता है।'

राजनीतिक संदेश या जनभावना?- इस पूरे घटनाक्रम ने बैकुंठपुर की राजनीति में नया विमर्श खड़ा कर दिया है, एक ओर भाजपा के स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर उपेक्षा का आरोप लगाया जा रहा है,तो दूसरी ओर इसे अनावश्यक राजनीतिक रंग देने का प्रयास भी कहा जा रहा है, कुछ लोगों का मत है कि बोर्ड टूटना एक प्रशासनिक चूक थी, जिसे अब सुधार दिया गया है, वहीं अन्य नागरिक इसे प्रतीकात्मक असंवेदनशीलता मानते हैं,जो बताती है कि स्मारकों और नामकरण के निर्णयों का पालन व्यवहार में कितना हो रहा है।

जनता की प्रतिक्रिया-शहरवासियों का कहना है कि स्वर्गीय तीरथ गुप्ता जी का योगदान किसी एक दल तक सीमित नहीं था, उनके नाम पर बने कॉम्प्लेक्स का सम्मान करना पूरी नगर परिषद और प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है, स्थानीय व्यापारी और नागरिक अब यह अपेक्षा जता रहे हैं कि शहर में अन्य स्मारकों और नामपट्टों की भी नियमित देखरेख हो, ताकि ऐसी स्थिति दोबारा न बने।

CMYK

सूरजपुर का 'धान गणित'

कमी से बराबरी तक, जांच से जीरो तक- ऊपर से नीचे तक सवाल ही सवाल

भौतिक सत्यापन में कमी, दूसरे में बराबरी- सूरजपुर के धान केंद्रों में कैसा खेल?

शॉर्टेज से 'सेटिंग' तकः क्या सूरजपुर में धान घोटाले को मिला संरक्षण?

-संवाददाता-
सूरजपुर, 24 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

जिले के धान खरीदी केंद्रों में सामने आया शॉर्टेज प्रकरण अब सिर्फ अनियमितता का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और व्यवस्था की विश्वसनीयता की अग्निपरीक्षा बन गया है, पहले भौतिक सत्यापन में हजारों बोरी धान कम मिला, संयुक्त जांच टीम ने गंभीर कमी दर्ज की, करोड़ों रुपये के संभावित नुकसान का अनुमान लगाया गया—और फिर अचानक दूसरे सत्यापन में सब कुछ बराबर हो गया, अब सवाल यह है कि आखिर यह पूरा गणित कैसे बदला? क्या सचमुच स्टॉक की भरपाई हुई, या फिर रिकॉर्ड का संतुलन बैठाया गया?

बता दे की जिले के धान खरीदी केंद्रों में सामने आए भारी शॉर्टेज के बाद प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, संयुक्त जांच टीम की रिपोर्ट में 8 उपार्जन केंद्रों में लगभग 37 हजार क्विंटल से अधिक धान की कमी पाई गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी अनियमितता के बावजूद अब तक केवल दो समितियों पर ही सीमित कार्रवाई हुई है, जबकि बाकी मामलों में ठोस कदम नजर

धान का गणितः पहले 37 हजार क्विंटल कम, फिर सब 'जीरो'- सूरजपुर में चमत्कार या मैनेजमेंट?

कमी की रिपोर्ट, फिर जीरो का आदेश- किसके इशारे पर बदला धान का हिसाब?

धान गायब, जवाब भी गायबः

सूरजपुर में कांग्रेस के दो चेहरे : एक नेता जांच पर सवाल उठाए तो दूसरा दोषियों पर कार्रवाई की मांग करता नजर आया...

धान घोटाले पर कांग्रेस के भीतर ही मतभेद,प्रशासन असमंजस में

वह केवल लापरवाही नहीं,सुनियोजित घोटाला है : जफर हैदर

पहले करोड़ों का घाटा, फिर सब संतुलित- क्या यह प्रशासनिक गणित है?

सूरजपुर में धान का जादुई हिसाबः कमी भी हमारी, बराबरी भी हमारी

निलंबन, एफआईआर और फिर सन्नाटा- धान खरीदी में ऊपर से

घटती-घटना
अम्बिकापुर,बुधवार 28 जनवरी 2026
4

13 हजार बोरियां कैसे गायब हुईं और फिर कैसे पूरी हो गईं?

शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र : दो जांच,दो नतीजे-सिस्टम कटघरे में

घटती-घटना
सरगुजा - अंतर्राष्ट्रीय समाचार
अम्बिकापुर,रविवार 25 जनवरी 2026
4

13 हजार क्विंटल की कमी के बाद 35 हजार क्विंटल की तेजी,संयोग या संकेत?

धान से बड़ा सवाल- व्यवस्था की विश्वसनीयता-

सूरजपुर का यह प्रकरण केवल धान की बोरी का नहीं, बल्कि प्रशासनिक विश्वसनीयता का मामला है, पहले कमी, फिर बराबरी, पहले सख्ती, फिर शांति, पहले शॉर्टेज, फिर जीरो, इन तीन चरणों के बीच जो अंतर है, वही असली कहानी है, यदि प्रशासन निष्पक्ष है, तो उसे तथ्यों के साथ सामने आना चाहिए, यदि गड़बड़ी हुई है, तो दोषियों पर समान कार्रवाई होनी चाहिए—चाहे वह नीचे के स्तर पर हों या ऊपर के, क्योंकि अंततः सवाल धान का नहीं, जनता के भरोसे का है, और भरोसा एक बार कम हो जाए, तो उसे दोबारा जीरो से भरना आसान नहीं होता।

क्या होनी चाहिए आगे की कार्रवाई?

दोनों भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।

स्वतंत्र ऑडिट या उच्चस्तरीय जांच कराई जाए।

परिवहन और गोदाम स्तर पर भी जवाबदेही तय हो।

निलंबित अधिकारियों को समिति से पूर्णतः पृथक रखा जाए।

दोष सिद्ध होने पर कठोर कानूनी कार्रवाई हो।

जांच में उजागर हुआ भारी शॉर्टेज-

संयुक्त जांच में जिले के कई उपार्जन केंद्रों में हजारों बोरी धान की कमी दर्ज की गई, अनुमानित तौर पर 37 हजार क्विंटल से अधिक धान का शॉर्टेज सामने आया, यह कोई छोटी-मोटी त्रुटि नहीं थी, बल्कि करोड़ों रुपये के संभावित नुकसान का संकेत था, इसके अलावा कुछ अन्य केंद्रों—जैसे रामानुजनगर विकासखंड के छिंदिया उपार्जन केंद्र—में भी हजारों बोरी धान की कमी का उल्लेख बताया गया, ऐसे में उम्मीद थी कि कठोर कार्रवाई होगी और जिम्मेदारों की जवाबदेही तय की जाएगी।

संयुक्त जांच टीम की रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े

उपार्जन केंद्र	बोरी	अनुमानित मात्रा (क्विंटल)
सावारावा	6,470	2,588
टुकूडांड	16,032	6,412.8
शिवप्रसादनगर	13,880	5,552
सूरजपुर	16,526	6,610.4
उमेश्वरपुर	17,591	7,630
सोनपुर	10,484	4,100
चंदौरा	2,045	818
लटोरी	10,919	4,367.6

कुल मिलाकर 37,000 क्विंटल से अधिक धान की कमी दर्ज की गई।

इसके अलावा रामानुजनगर विकासखंड के छिंदिया उपार्जन केंद्र में भी लगभग 3,000 बोरी धान कम पाए जाने का उल्लेख ज्ञापन और जांच रजिस्टर में दर्ज बताया जा रहा है, लेकिन वहां भी अब तक स्पष्ट कार्रवाई सामने नहीं आई है।

कार्रवाई या लीपापोती?-

सूत्रों के अनुसारः उमेश्वरपुर में जिम्मेदारों पर एफआईआर दर्ज की गई है, सावरावा में एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी हुआ, लेकिन अब तक अपराध पंजीबद्ध नहीं हुआ, अन्य केंद्रों में प्रभारियों को निलंबित किया गया, लेकिन वे कथित रूप से अब भी समितियों में सक्रिय हैं और धान उठाव व खरीदी कार्य में भूमिका निभा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब निलंबन हुआ है तो संबंधित प्रभारी उसी समिति में किस हैसियत से कार्य कर रहे हैं?

कलेक्टर के संदेश पर भी सवाल-

सूत्रों का दावा है कि निरीक्षण के दौरान यह संदेश दिया गया कि धान की खरीदी और उठाव जीरो होना चाहिए, अब प्रश्न यह उठता है, क्या यह जीरो करने का निर्देश कमी को कागजों में शून्य करने की ओर संकेत था? क्या शॉर्टेज की भरपाई का समय देकर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? या फिर राजनीतिक संरक्षण के चलते कार्रवाई सीमित रखी गई?

करोड़ों का नुकसान, जिम्मेदारी किसकी?-

इतनी बड़ी मात्रा में धान की कमी से सीधे तौर पर सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का संभावित नुकसान है, यदि संयुक्त जांच टीम की रिपोर्ट सही है, तो यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि सुनियोजित गड़बड़ी की ओर इशारा करती है, ऐसे में सवाल उठता है कि—क्या सभी दोषियों पर समान कार्रवाई होगी?क्या उच्चस्तरीय स्वतंत्र जांच की मांग की जाएगी? या फिर मामला समय के साथ ठंडे बस्ते में चला जाएगा?

कार्रवाई की शुरुआत, फिर ठहराव-

प्रारंभिक चरण में कुछ समितियों के प्रभारियों को निलंबित किया गया, एक-दो स्थानों पर एफआईआर दर्ज हुई या दर्ज करने के आदेश दिए गए, लेकिन धीरे-धीरे कार्रवाई का दायरा सिमटता नजर आया, जहां 8 से 10 समितियों में शॉर्टेज की चर्चा थी, वहां वास्तविक कानूनी कार्रवाई सीमित रह गई, स्थानीय स्तर पर आरोप यह भी है कि निलंबित प्रभारी अब भी उसी समिति में सक्रिय दिखे, धान उठाव और रिकॉर्ड प्रक्रिया में उनकी भूमिका बनी रही, यदि यह सच है, तो यह नियमों और प्रशासनिक मर्यादा दोनों पर प्रश्नचिह्न है।

दोबारा भौतिक सत्यापनः आवश्यकता या अवसर?-

सबसे बड़ा विवाद दूसरे भौतिक सत्यापन को लेकर है, पहले सत्यापन में कमी दर्ज हुई, मीडिया में खबरें आईं, जनता में चर्चा तेज हुई, और फिर हुआ दोबारा सत्यापन, परिणाम—कई जगह स्टॉक बराबर, अब यहां से शुरू होता है असली सवालों का दौर, क्या पहली जांच में तकनीकी त्रुटि थी? यदि थी, तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं? यदि पहली रिपोर्ट सही थी, तो अचानक कमी कैसे खत्म हो गई? क्या भरपाई कराई गई? यदि हां, तो वह धान आया कहां से? दूसरा सत्यापन यदि पारदर्शी प्रक्रिया का हिस्सा था, तो उसकी विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई?

जीरो का संदेशः प्रशासनिक लक्ष्य या संकेत?-

निरीक्षण के दौरान कथित तौर पर यह संदेश दिया गया कि धान की खरीदी और उठाव जीरो होना चाहिए, यह वाक्य अब पूरे विवाद का केंद्र बन गया है, क्या इसका अर्थ था—शॉर्टेज खत्म कर संतुलन बनाओ? या रिकॉर्ड में कमी शून्य दिखाओ? प्रशासन की ओर से यदि इसका स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं आता, तो यह कथन संदेह को और गहरा करता है।

परिवहन, गोदाम और समिति—कड़ी दर कड़ी-

धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया कई स्तरों से गुजरती है, किसान से खरीदी, समिति में भंडारण, परिवहन के माध्यम से गोदाम तक पहुंचाना, रिकॉर्ड मिलान, यदि इतनी बड़ी मात्रा में शॉर्टेज पाया गया, तो जिम्मेदारी सिर्फ समिति प्रभारी तक सीमित नहीं हो सकती, क्या परिवहन में हेराफेरी हुई? क्या गोदाम स्तर पर स्टॉक एंट्री में अंतर था? क्या निगरानी तंत्र ने समय पर संकेत नहीं पकड़ा? यह जांच ऊपर से नीचे तक होनी चाहिए थी।

प्रशासनिक जवाबदेहीः शीर्ष से जमीनी स्तर तक-

किसी भी जिले में धान खरीदी राज्य सरकार की प्राथमिक योजनाओं में से एक होती है। इसकी निगरानी जिला प्रशासन के शीर्ष अधिकारी—कलेक्टर—के अधीन होती है, यदि इतने बड़े पैमाने पर शॉर्टेज हुआ, तो यह केवल जमीनी कर्मचारियों की गलती नहीं हो सकती, हालांकि बिना ठोस प्रमाण किसी अधिकारी की भूमिका पर सीधा आरोप लगाना उचित नहीं, लेकिन यह भी जरूरी है कि, कलेक्टर कार्यालय विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक करे, दोनों भौतिक सत्यापन की तुलना सामने लाए, स्पष्ट करे कि किस आधार पर मामला संतुलित माना गया, यदि शीर्ष स्तर से स्पष्टता आएगी, तो नीचे के स्तर पर उठ रहे सवाल भी शांत होंगे।

मीडिया और जनदबाव की भूमिका-

इस पूरे प्रकरण में मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही, खबरें सामने आईं, आंकड़े सार्वजनिक हुए, और जनचर्चा तेज हुई, प्रश्न यह है कि यदि समाचार प्रकाशित न होते, तो क्या दूसरा सत्यापन होता? और यदि मीडिया के बाद सत्यापन हुआ, तो क्या यह दबाव का परिणाम था? पारदर्शी शासन में मीडिया और प्रशासन का रिश्ता टकराव का नहीं, जवाबदेही का होना चाहिए।

सरकारी खजाने और किसानों का भरोसा-

धान खरीदी सिर्फ आर्थिक लेन-देन नहीं है, यह किसानों के विश्वास और राज्य की साख का प्रश्न है, यदि कमी वास्तविक थी, तो यह सीधे सरकारी खजाने को नुकसान और किसानों के अधिकारों पर चोट है, यदि कमी बाद में समायोजित हुई, तो यह पारदर्शिता पर प्रश्न है, दोनों ही स्थितियां चिंताजनक हैं।

छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 पर सूरजपुर में सियासी संग्राम

भाजपा ने बताया विकास का रोडमैप,कांग्रेस ने कहा जनता के साथ छल

-ओंकार पाण्डेय-
सूरजपुर,24 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 के 1.72 लाख करोड़ के बजट को लेकर जिले में सत्तापक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं, एक ओर भाजपा इसे विकसित छत्तीसगढ़ 2047 का संकल्प बजट बता रही है,तो वहीं कांग्रेस ने इसे छलावा,झुनझुना और जुमला बजट करार दिया है। छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 पर सूरजपुर में स्पष्ट राजनीतिक विभाजन दिख रहा है,कांग्रेस इसे जनविरोधी और दिखावटी बता रही है,जबकि भाजपा इसे आत्मनिर्भर और विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला मान रही है,अब नजर इस बात पर रहेगी कि बजट की घोषणाएं धरातल पर कितनी प्रभावी साबित होती हैं और जनता को वास्तविक लाभ कितना मिलता है।

नीचे बजट पर आई सभी प्रमुख राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्रमवार प्रस्तुत हैं...

भाजपा की प्रतिक्रियाएं...

जनआकांक्षाओं का बजटः भूलन सिंह मरावी

प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट गांव, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं को सशक्त करने वाला है, उन्होंने कहा कि सिंचाई विस्तार, कृषि अधोसंरचना और ग्रामीण सड़कों के विकास से प्रदेश को नई गति मिलेगी।

युवाओं के सपनों को उड़ान : देव गुप्ता

भाजयुमो जिलाध्यक्ष देव गुप्ता ने इसे अमृत बजट बताया, उन्होंने कहा कि शिक्षा,स्टार्टअप, कौशल विकास और अधोसंरचना विस्तार युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगा।

सामाजिक-आर्थिक विकास का बजट : शंकर जिंदी

भाजपा नेता शंकर जिंदी ने कहा कि यह तीसरा बजट प्रदेश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति देने वाला है। कृषक उन्नति योजना,खाद्यान्न सहायता, आवास और ऊर्जा सब्सिडी जैसे प्रावधान सराहनीय हैं।

समावेशी विकास : संदीप अग्रवाल

भाजपा जिला कोषाध्यक्ष संदीप अग्रवाल ने कहा कि यह बजट सुशासन और समृद्धि का आधार बनेगा।

आर्थिक अनुशासन और विकास : रितेश गुप्ता

आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक रितेश गुप्ता ने कहा कि बजट में वित्तीय अनुशासन और विकास का संतुलन है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।

संतुलित और दूरदर्शी : शशिकांत गर्ग

भाजपा जिला महामंत्री शशिकांत गर्ग ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और उद्योग के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

आस्था और विकास का संगम : बाबूलाल अग्रवाल

निवृतमान जिलाध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल ने बताया कि मां कुदरगढ़ी धाम को शक्तिपीठ सर्किट में शामिल कर 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है और रोपवे निर्माण से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

आमजन की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगाः मुरली मनोहर सोनी

भाजपा जिला अध्यक्ष मुरली मनोहर सोनी ने इसे ऐतिहासिक बजट बताया और कहा कि यह गांव, गरीब और किसान केंद्रित है।

किसानों-युवाओं के लिए भरोसे का बजट : राजेश्वर तिवारी

भाजपा जिला मंत्री राजेश्वर तिवारी ने कहा कि कृषक उन्नति योजना, बिजली सब्सिडी और ब्याज-मुक्त ऋण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 ऐतिहासिक और दूरदर्शी : विधायक शकुंतला सिंह

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 का प्रतापपुर विधायक शकुंतला सिंह ने स्वागत करते हुए इसे सर्वांगीण विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित बताया, उन्होंने कहा कि बजट किसानों, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और अधोसंरचना विकास को नई दिशा देगा। यह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना को साकार करने वाला बजट है, विधायक ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व की सराहना करते हुए विश्वास जताया कि यह बजट विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को मजबूत आधार देगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं...

महिलाओं व आम जनता के साथ छलावाःभगवती राजवाड़े

पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष भगवती राजवाड़े ने कहा कि यह बजट महिलाओं और आम जनता के साथ छल करने जैसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने पिछले दो वर्षों में आमजन के हित में कोई ठोस कार्य नहीं किया और चुनावी वादों को भूल गई है।

किसानों के लिए बजट में झुनझुनाःअश्विनी सिंह

पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अश्विनी सिंह ने कहा कि किसानों को इस बजट में कोई ठोस राहत नहीं दी गई। धान खरीदी में अव्यवस्थाओं से परेशान किसानों के लिए बजट में ठोस प्रावधान नहीं दिखता।

शहरों के लिए कुछ नहींःमनोज डालमिया

शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज डालमिया ने कहा कि शहरों में सड़क, नाली और पानी की समस्या गंभीर है, लेकिन बजट में शहरी विकास के लिए कोई नई योजना नहीं है।

ढकोसला बजटःजफर हैदर

ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जफर हैदर ने कहा कि बजट में कुछ भी नया नहीं है, केवल पुरानी योजनाओं को दोहराया गया है। किसान, युवा और मजदूर वर्ग इससे निराश है।

युवा व छात्र विरोधी बजटःआकाश साहू

एनएसयूआई जिलाध्यक्ष आकाश साहू ने कहा कि प्रदेश में स्कूल और कॉलेज भवन जर्जर हैं, लेकिन उनके सुधार के लिए स्पष्ट योजना नहीं है। बेरोजगारी की समस्या पर भी कोई ठोस रोडमैप नहीं दिखता।

किसान विरोधी बजटःविमलेश तिवारी

छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष विमलेश तिवारी ने कहा कि उद्योगों और मशीन निर्माण कंपनियों के लिए बड़ी राशि रखी गई है,लेकिन किसानों को सीधा लाभ देने का स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

बड़ा आंकड़ा,छोटी राहतःसंजय दोषी

कांग्रेस जिला महामंत्री संजय दोषी ने 1.72 लाख करोड़ के बजट को बड़ा आंकड़ा,छोटी राहत बताया, उन्होंने कहा कि एमएसपी, कर्ज राहत और युवाओं की भर्तियों का कोई स्पष्ट कैलेंडर नहीं है। यह बजट घोषणाओं का संग्रह है,जमीन पर बदलाव का नहीं।

सूरजपुर की उम्मीदों पर फिरा पानी... शशि सिंह ने बजट को बताया छलावा

छत्तीसगढ़ सरकार के वर्ष 2026-27 के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि सिंह ने इसे दिशाहीन और जनविरोधी करार दिया है,उन्होंने कहा कि बजट केवल आंकड़ों और विज्ञापनों तक सीमित है,जबकि आम जनता, किसान और युवाओं के लिए कोई ठोस पहल नहीं दिखती, शशि सिंह ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के गृह संभाग से जुड़े क्षेत्र होने के बावजूद सूरजपुर जिले को स्वास्थ्य,मेडिकल कॉलेज और अधोसंरचना के मामले में अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिली,उन्होंने कहा कि किसानों के लिए खाद-बीज, धान बोनस और आय वृद्धि को लेकर स्पष्ट नीति का अभाव है,वहीं महंगाई पर सरकार मौन है, कांग्रेस के अनुसार यह बजट विकसित छत्तीसगढ़ नहीं,बल्कि विज्ञापनी छत्तीसगढ़ का बजट है।

1.72 लाख करोड़ का 'संकल्प' बजट

स्वास्थ्य,उद्योग,शिक्षा पर जोर...कोरिया को बड़ी घोषणा नहीं,नेताओं की मिली-जुली प्रतिक्रिया

-संवाददाता-
कोरिया/ एमसीबी,24 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया, 'संकल्प' थीम पर आधारित इस बजट को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास का रोडमैप बताया गया है, बजट में उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। हालांकि कोरिया जिले के लिए बड़ी परियोजना की घोषणा नहीं होने से स्थानीय स्तर पर चर्चा भी तेज है। प्रदेश स्तर पर बजट का आकार बड़ा और घोषणाएं व्यापक हैं, भाजपा इसे विकास और संकल्प का बजट बता रही है,वहीं कांग्रेस इसे जनविरोधी और घोषणात्मक बजट करार दे रही है,कोरिया जिले को सीमित सौगात मिलने से स्थानीय स्तर पर असंतोष की चर्चा भी बनी हुई है,अब नजर इस पर रहेगी कि बजट की घोषणाएं धरातल पर कितनी तेजी से उतरती हैं और क्या भविष्य में जिले को अतिरिक्त लाभ मिलता है।

बजट की प्रमुख घोषणाएं

बेटियों के लिए सौगात
18 वर्ष पूर्ण करने पर बालिकाओं को 1.5 लाख देने की घोषणा।

किसानों के लिए
ब्याज मुक्त ऋण योजना जारी।
सहकारी समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित करने की पहल।

औद्योगिक विकास
प्रदेश में 23 नए उद्योग स्थापित होंगे।
निवेश प्रोत्साहन हेतु 100 करोड़ का प्रावधान।
पांच शहरों के एयरपोर्ट पर शोरूम निर्माण।

स्वास्थ्य
रायपुर में 200 बिस्तर का अस्पताल।
मनेंद्रगढ़-चिरमिरी में जिला अस्पताल।
कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार योजना (?100 करोड़ प्रावधान)।

वन संरक्षण
वनों के संरक्षण के लिए 930 करोड़ का प्रावधान।

शिक्षा व भर्ती
स्कूल शिक्षा विभाग को ?22 हजार करोड़।
स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना हेतु ?100 करोड़।
1,000 पदों पर भर्ती।

प्रमुख मिशन
मुख्यमंत्री एआई मिशन
मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन
मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन
मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन
मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन
(प्रत्येक के लिए 100 करोड़)

जनप्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया

भाजपा पक्ष

देवेन्द्र तिवारी (भाजपा जिलाध्यक्ष)

उन्होंने बजट को 'संकल्प का बजट' बताते हुए कहा कि राज्य का बजट आकार निरंतर बढ़ा है और यह विकास की गति को और तेज करेगा। उन्होंने बताया कि कोरिया जिले के बैकुण्ठपुर में गेज डैम उन्नयन के लिए 10 करोड़ की स्वीकृति मिली है।

शारदा गुप्ता (जिलाध्यक्ष, चेम्बर ऑफ कॉमर्स)

उन्होंने बजट की सराहना करते हुए कहा कि निवेश, सड़क कनेक्टिविटी और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं और युवाओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे बाजार में आर्थिक गतिविधि तेज होगी।

भैयालाल राजवाड़े (विधायक बैकुण्ठपुर)

उन्होंने गेज डैम उन्नयन के लिए 10 करोड़ की स्वीकृति को किसानों और पर्यटन के लिए बड़ी सौगात बताया। कहा कि डबल इंजन सरकार में विकास की रफ्तार तेज होगी और कोरिया मुख्यधारा में आगे बढ़ेगा।

श्याम बिहारी जायसवाल (स्वास्थ्य मंत्री)

उन्होंने बजट को राज्य के लिए लाभदायक और हर वर्ग के लिए बेहतर बताया। कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा को ऐतिहासिक निर्णय कहा। स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े प्रावधानों पर मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का आभार जताया।

कांग्रेस पक्ष

गुलाब कमरो (पूर्व विधायक)

उन्होंने बजट को घोषणाओं का पुलिंदा बताते हुए कहा कि किसानों, युवाओं और गरीबों के लिए ठोस राहत का अभाव है। महंगाई और रोजगार पर स्पष्ट नीति नहीं है।

प्रदीप गुप्ता (जिला कांग्रेस अध्यक्ष)

उन्होंने बजट को पूंजीपतियों का हितैषी बताया और कहा कि आम आदमी की रसोई और युवाओं की नौकरी के लिए कोई ठोस योजना नहीं है।

योगेश शुक्ला (वरिष्ठ कांग्रेस नेता)

उन्होंने इसे 'आंकड़ों की बाजीगरी' करार देते हुए कहा कि गरीब, किसान और युवाओं के लिए राहत के नाम पर कुछ नहीं है।

वेदांती तिवारी (पूर्व उपाध्यक्ष, जिला पंचायत कोरिया)

उन्होंने बजट को जनविरोधी और दिशाहीन बताया तथा ग्रामीण और आदिवासी अर्थव्यवस्था की उपेक्षा का आरोप लगाया।

अंबिका सिंह देव (पूर्व विधायक बैकुण्ठपुर)

उन्होंने कहा कि कोरिया और उत्तरी छत्तीसगढ़ के लिए कोई विजनरी योजना नहीं दिखी। रोजगार और किसानों की आय बढ़ाने पर स्पष्ट रोडमैप का अभाव है।

कोरिया जिले के हिस्से में क्या?

स्थानीय स्तर पर बैकुण्ठपुर गेज डैम उन्नयन के लिए ?10 करोड़ की घोषणा सामने आई है। इसके अलावा जिले के लिए कोई बड़ी औद्योगिक, स्वास्थ्य या अधोसंरचना परियोजना घोषित नहीं हुई है।

ज्योत्स्ना महंत (सांसद)

सांसद ज्योत्स्ना महंत ने राज्य बजट 2026-27 पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा जिसे 'संकल्प' बता रही है,वह वास्तव में दिशाहीन और निराशाजनक बजट है, उन्होंने कहा कि बजट में बेरोजगारों के लिए नौकरी का कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं है और महिलाओं की सुरक्षा व आत्मनिर्भरता को लेकर ठोस योजना का अभाव है। महतारी वंदन योजना को उन्होंने केवल औपचारिकता बताया,सांसद महंत ने आरोप लगाया कि किसानों के कर्ज और लागत कम करने के लिए कोई प्रभावी प्रावधान नहीं है, डबल इंजन सरकार के बावजूद बिजली बिल और पेट्रोल-डीजल के टैक्स में राहत नहीं दी गई, उन्होंने कहा कि उनके लोकसभा क्षेत्र के जिलों के लिए किसी विशेष पैकेज की घोषणा नहीं होना सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़ा करता है,यह बजट विकास का नहीं, बल्कि जनता को निराश करने वाला दस्तावेज है,उन्होंने कहा।

13 साल की उम्र में पर्दे पर बनी मां...6 दशक तक सिनेमा में किया राज...रहस्यमयी रही एक्ट्रेस की मौत

सिनेमा जगत की एक दिग्गज अदाकारा की डेथ एनिवर्सरी मनाई गई। इस अभिनेत्री ने 6 दशक से ज्यादा लंबे समय तक इंडस्ट्री में राज किया था और उन्हें लेडी सुपरस्टार की उपाधि भी मिली थी।

8 साल पहले आज ही के दिन सिनेमा जगत की एक मशहूर अभिनेत्री ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनकी मौत बड़ी ही रहस्यमयी रही थी। करीब 6 दशकों तक बतौर एक्ट्रेस इंडस्ट्री में राज करने वाली इस हसीना ने महज 13 साल की उम्र में बड़े पर्दे पर मां की भूमिका निभाकर हर किसी को हैरान कर दिया था।

ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां कौन सी अदाकारा के बारे में जिक्र किया जा रहा है, जो साउथ से लेकर हिंदी सिनेमा तक लेडी सुपरस्टार के तौर पर जानी गईं।

लेडी सुपरस्टार की डेथ एनिवर्सरी

जिस अभिनेत्री के बारे में इस लेख में जिक्र किया जा रहा है, उसे सिनेमा की चांदनी कहा जाता था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहां बात वेटरन एक्ट्रेस श्रीदेवी के बारे में की जा रही है।

24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी का निधन हुआ था। दुबई के एक होटल के बाथरूम में बाथटब में डूबने से हुई थी। उनकी मौत भी काफी रहस्यमयी रही, पति बोनी कपूर ने बताया था अत्यधिक डाइटिंग की वजह से उनका देहांत हुआ था।

13 साल की उम्र में निभाया मां का किरदार

बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट श्रीदेवी ने सिनेमा जगत में अपना सफर शुरू किया था। लेकिन उनको सबसे अधिक लाइमलाइट 13 साल की उम्र में मां का किरदार निभाने से मिली थी। साउथ सिनेमा के मशहूर निर्देशक रहे बालचंदर के निर्देशन में बनी फिल्म मंदरू मुदिचू में श्रीदेवी ने सुपरस्टार रजनीकांत की मां की भूमिका निभाई थी। इसके बाद श्रीदेवी और रजनीकांत लगभग 20 फिल्मों में एक साथ काम किया।

6 दशक तक सिनेमा जगत में किया राज

श्रीदेवी मूलरूप से साउथ सिनेमा से नाता रखती थीं। हिंदी सिनेमा में डेब्यू से पहले उन्होंने साउथ सिनेमा की मूवीज में अपना जलवा बिखेरा था। इस दौरान कई दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम किया। इस तरह से बतौर एक्ट्रेस श्रीदेवी ने अपने 6 दशक से लंबे फिल्मी करियर में करीब 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। उनकी लोकप्रिय हिंदी मूवीज के बारे में जिक्र किया जाए तो उनमें तोहफा,नागिना, निगाहें,मिस्टर इंडिया,चालबाज,चांदनी, खुदा गवाह, जुदाई,लाडला,इंग्लिश विंग्लिश और मॉम जैसी कई शानदार फिल्मों के नाम शामिल रहे।

नील नितिन मुकेश के साथ हुई धोखाधड़ी

एक्टर ने झटके में तोड़ी करोड़ों की डील

नील नितिन मुकेश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने एक सिंगिंग रियेलिटी शो से नाता तोड़ दिया है। अभिनेता ने ऑर्गनाइर्स पर धोखा देने का आरोप लगाया है और सीधे तौर पर शो से अलग होने का ऐलान कर दिया है। बतौर चाइल्ड एक्टर अपना करियर शुरू करने वाले नील नितिन मुकेश बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक में अपनी पहचान बना चुके हैं। इस बीच अभिनेता एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार नील किसी फिल्म को लेकर नहीं बल्कि अपने एक पोस्ट को लेकर सुर्खियों में हैं। नील नितिन मुकेश ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया है कि वह सिंगिंग रियेलिटी शो द यूनिवर्सल आइडल से नाता तोड़ रहे हैं। जी हां, अभिनेता ने सिंगिंग रियेलिटी शो की ब्रांड एंबेसडरशिप छोड़ने का ऐलान किया है। इसी के साथ अभिनेता ने ऑर्गनाइजर्स पर पर फीस का भुगतान न करने का आरोप लगाया है और साथ ही इंडस्ट्री के अन्य कलाकारों को भी इस तरह के धोखे से बचकर रहने के लिए आगाह किया है। एक्टर ने बताया कि कई बार उन्हें आश्वासन दिया गया, लेकिन इसके बावजूद उनका भुगतान नहीं किया गया।

नील नितिन मुकेश के साथ हुआ धोखा

नील नितिन मुकेश ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक बयान साझा किया। इसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने एचएमसी इवेंट्स से जुड़े शो द यूनिवर्सल आइडल से अलग होने का फैसला लिया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, मैं औपचारिक रूप से एचएमसी इवेंट्स के 'द यूनिवर्सल आइडल' में ब्रांड एंबेसडर के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। कई बार वादा करने के बावजूद मुझे तय किए गए भुगतान की राशि नहीं दी गई। जो तीन चेक दिए गए थे, वे भी बाउंस हो गए। यह भरोसे और जिम्मेदारी की गंभीर कमी को दिखाता है। मेरी टीम और मैंने इस मुद्दे को शांति से सुलझाने के लिए कई बार संपर्क किया और मौका दिया, लेकिन अफसोस की बात है कि कोई समाधान नहीं निकला।

लीगल एक्शन लेंगे नील नितिन मुकेश?

अभिनेता ने इस पोस्ट में आगे लिखा- इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यूनिवर्सल आइडल, एचएमसी इवेंट्स और श्री शकील हासन और उनके सहयोगियों के साथ अपने सभी मौजूदा और भविष्य के संबंधों से तत्काल प्रभाव से अलग हो रहा हूं। यह नोट इसलिए शेयर कर रहा हूं कि अन्य कलाकार, वेंडर्स और पार्टनर्स सावधान रहें और किसी भी तरह के दावे, वादे और पेमेंट की पूरी जांच-पड़ताल करें। मैं कानून के तहत उपलब्ध उचित उपायों का पालन करने के सभी अधिकार सुरक्षित रखता हूं।

नील नितिन मुकेश का करियर

बता दें कि नील नितिन मुकेश ने जॉनी गद्दार से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने अपने करियर में न्यूयॉर्क,प्लेयर्स, लफंगे परिंदे, प्रेम रतन धन पायो,वजीर,साहो, जेल और इंदु सरकार जैसी फिल्मों में काम किया। वहीं उनकी अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो अब वह जल्द ही मलयालम फिल्म खलीफा में नजर आने वाले हैं।

1000 करोड़ी फिल्म का आएगा सिक्वल

हो रही तैयारी,पर्दे पर छाएगी अमिताभ बच्चन और कमल हासन की जोड़ी...

पहले पार्ट ने मचाई थी बॉक्स ऑफिस पर तबाही

साल 2024 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी थी, अब इस फिल्म की सीक्वल रिलीज होने के लिए तैयारी कर रहा है। फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। कमल हासन और अमिताभ बच्चन की जोड़ी इस फिल्म में नजर आएगी।साल 2024 में एक मल्टी स्टारर फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सुपरस्टार की फौज थी,7 दमदार सितारों से सजी इस फिल्म की कहानी ने लोगों का दिल जीता और इसे देखने के लिए दर्शकों की भीड़ सिनेमाघरों में पहुंची। फिल्म ने धांसू कमाई करते हुए दुनिया भर में 1000 करोड़ के पार कलेक्शन कर लिया। स्टार पावर के साथ फिल्म में दिखाई गई अलग दुनिया से लोग प्रभावित हुए। सफलता के बाद मेकर्स ने इसके दूसरे पार्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। फिल्म के सीक्वल की शूटिंग शुरू हो चुकी है और इसकी झलक भी सामने आई है, जिसमें अमिताभ बच्चन और कमल हासन एक साथ नजर आ रहे हैं।

हैदराबाद में शूटिंग, इसलिए मिस हुआ रविवार

सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का हर रविवार उनके फैंस के नाम होता है। मुंबई स्थित उनके घर के बाहर सैकड़ों लोग सिर्फ एक झलक पाने के लिए इकट्ठा होते हैं। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग थी। काम की वजह से बिग बी अपने चाहने वालों से मुलाकात नहीं कर पाए। अपने लेटेस्ट ब्लॉग में अमिताभ बच्चन ने बताया कि वह हैदराबाद में कल्कि 2898,एडी के सीक्वल की शूटिंग में व्यस्त थे। उन्होंने घर के बाहर इंतजार करते फैंस की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि उन्होंने पहले ही सूचित कर दिया था कि वह इस रविवार नहीं आ पाएंगे, फिर भी लोग सिर्फ यह कन्फर्म करने के लिए पहुंच गए।

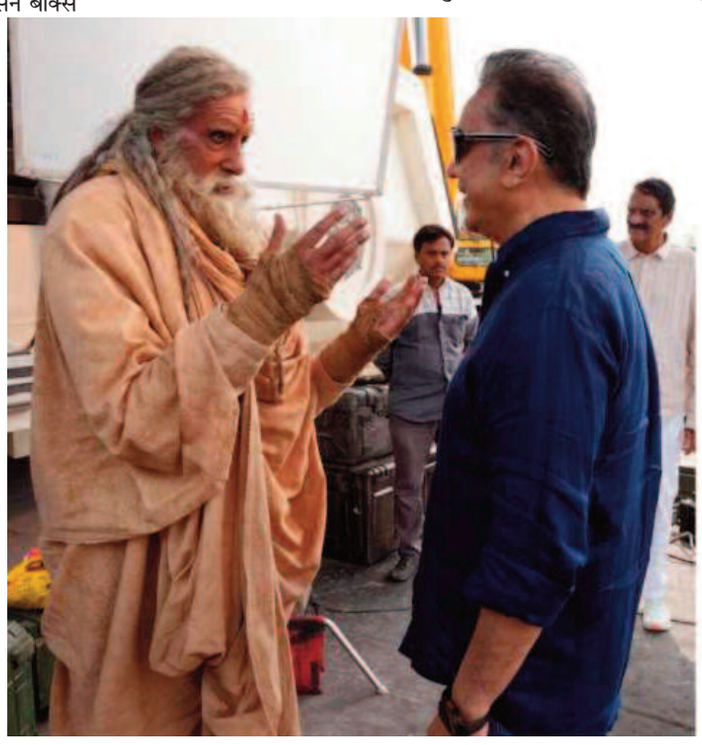

अश्वत्थामा लुक और कमल हासन संग रीयूनियन

उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह भी लिखा कि एक प्यारा सा कुत्ता भी उनसे मिलने आया था। साथ ही उन्होंने फैंस से माफी मांगते हुए कहा, पहले काम, फिर आराम। बिग बी ने फिल्म के सेट से कुछ बिहाइंड-द-सीन्स तस्वीरें भी शेयर कीं। इनमें उनका अश्वत्थामा वाला ट्रांसफॉर्मेशन लुक नजर आया। साथ ही एक तस्वीर में वह दिग्गज अभिनेता कमल हासन को गले लगाते दिखे। अमिताभ ने बताया कि वह कमल हासन के साथ लंबे समय बाद काम कर रहे हैं। इससे पहले दोनों फिल्म गिरफ्तार में साथ नजर आए थे। अब करीब तीन दशक बाद यह जोड़ी फिर बड़े पर्दे पर दिखेगी।

क्या खास होगा 'कल्कि 2' में?

पहली फिल्म में अमिताभ बच्चन ने अश्वत्थामा का किरदार निभाकर दर्शकों और समीक्षकों दोनों को प्रभावित किया था। कई लोगों का मानना था कि उन्होंने फिल्म में प्रभास से भी ज्यादा असर छोड़ा। हालांकि पहली किस्त में कमल हासन और बिग बी ने साथ कोई सीन शेयर नहीं किया था,लेकिन सीक्वल में दोनों के किरदारों को ज्यादा गहराई से दिखाया जाएगा। निर्देशक नाग अश्विन के मुताबिक़दूसरे पार्ट में कहानी का फोकस कर्ण और अश्वत्थामा पर ज्यादा रहेगा,और प्रभास का स्क्रीन टाइम भी बढ़ेगा। खबरें हैं कि पहली फिल्म में अहम भूमिका निभाने वाली दीपिका पादुकोण सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी,हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है।

रिकॉर्डतोड़ सफलता के बाद बढ़ी उम्मीदें

'कल्कि 2898 एडी' का पहला भाग बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था। फिल्म ने दुनियाभर में ` 1,042 करोड़ की कमाई की और साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल रही। अब जब सीक्वल पर काम शुरू हो चुका है, तो फैंस की उत्सुकता चरम पर है और जहां तक रविवार की मुलाकात की बात है, बिग बी ने वादा किया है कि आने वाले रविवार को वह अपने चाहने वालों से जरूर मिलेंगे।

फिल्मी खानदान की स्टार बेटी,जिसके नाम से जुड़ा हर चैप्टर रहा विवादित,नशे की लत ने किया परेशान

पूजा भट्ट ने बड़े फिल्ममेकर की बेटी होते हुए भी इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। पूजा भट्ट की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ हमेशा ही चर्चा में रही है। एक समय था जब वह सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रही थीं और तभी उन्हें शराब की लत लग गई, जिससे निकलने के लिए उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

पूजा भट्ट के पिता महेश भट्ट बॉलीवुड के जाने-माने डायरेक्टर हैं और अब तक दर्जनों फिल्में दे चुके हैं। पूजा ने भी अपने पिता की तरह फिल्मी दुनिया को अपने करियर का रास्ता बनाया। पूजा ने एक्टिंग के साथ डायरेक्शन और प्रोड्यूसर के तौर पर भी अपनी किस्मत आजमाई है। लेकिन पूजा भट्ट की ज़िंदगी हमेशा से ही विवादों में घिरी रही है। कभी अपने पिता के साथ ही आई तस्वीरों को लेकर लोगों ने खूब चर्चा की। कभी पूजा भट्ट खुद भी शराब के नशे से जूझती रहीं। वहीं अपनी लव लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रहीं। आज पूजा भट्ट का जन्मदिन है,इस मौके पर उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं।

शराब की लत से जूझ चुकी हैं पूजा भट्ट

बीते दिनों पूजा भट्ट ने अपनी शराब की लत को लेकर खुद भी शेयर किया था। शराब छोड़ने के 5 साल बाद पूजा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था। उन्होंने अतीत में शराब की लत से जूझने की बात स्वीकार की है और अपनी रिकवरी के बारे में भी खुलकर बात की है।इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में, पूजा ने उस समय को याद किया जब वह प्यार की तलाश में भटक रही थीं और कहा कि कुछ साल पहले उन्हें अपने जीवन का प्यार मिला-नशामुक्ति। उन्होंने लिखा, मुझे याद नहीं कि कब मुझे प्यार नहीं हुआ। लोगों से, हां... लेकिन उससे भी ज्यादा प्यार के विचार से। मैं जहां भी गई, प्यार की तलाश करती रही। आधी रात को अनजान रास्तों पर, यहां तक कि देशों, सीमाओं और महाद्वीपों को पार करते हुए भी, मैंने प्यार का पीछा किया। मैं अपने आप को उन लोगों का बहुत बड़ा श्रेय देती हूं जिन्होंने मुझसे प्यार किया और खासकर उनका जिन्होंने नहीं किया।

खेल समाचार

एलएसजी ने आईपीएल 2026 से पहले अपना नया लोगो जारी किया

नई दिल्ली,24 फरवरी 2026। लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) ने इस साल इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सीजन से पहले अपना नया लोगो जारी किया। अपने आधिकारिक बयान में, एलएसजी ने अपने लोगो के बारे में कहा कि यह शहर, राज्य और उन प्रशंसकों की भावना को दर्शाता है जो शुरुआत से ही फ्रेंचाइजी के साथ खड़े रहे हैं, तीन प्रतीकों -गरुड़,मुकुट और हाथी-को एक साथ लाकर,जिनमें से प्रत्येक उत्तर प्रदेश के बारे में एक गहरी व्यक्तिगत कहानी बताता है। आज लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक नया लोगो जारी किया है। यह सिर्फ एक नया डिज़ाइन या नया रूप नहीं है। बल्कि यह एक ऐसा प्रतीक है जो इस शहर,इस राज्य और हर उस प्रशंसक की भावना को दर्शाता है जो शुरुआत से ही टीम के साथ खड़ा रहा है। यह नया प्रतीक तीन शक्तिशाली प्रतीकों-गरुड़,मुकुट और हाथी-को एक साथ लाता है,जिनमें से प्रत्येक लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लिए एक गहरी व्यक्तिगत कहानी कहता है,एलएसजी के बयान में कहा गया है। लोगो में निहित प्रतीकों के बारे में विस्तार से बताते हुए एलएसजी ने कहा, गरुड़ साहस का प्रतीक है। उठने का,चुनौतियों का सामना करने का और कभी पीछे न हटने का साहस। यह उस निडर क्रिकेट को दर्शाता है जिसे सुपर जायंट्स खेलने का प्रयास करते हैं और इस विश्वास को कि जब आप एक साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता। मुकुट गौरव और जिम्मेदारी का प्रतीक है। हर बार जब टीम मैदान पर उतरती है, तो वह लाखों की उम्मीदों को अपने साथ लेकर चलती है। मुकुट इस बात की याद दिलाता है कि इस जर्सी को पहनना एक सम्मान है और यह सम्मान हर दिन अर्जित करना पड़ता है।

फेडरेशन से नाराज पाकिस्तान हॉकी टीम

वर्ल्ड कप क्वालीफायर के लिए मिस रवाना

मुंबई,24 फरवरी 2026। एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान की नाराज हॉकी टीम वर्ल्ड कप क्वालीफायर के लिए मिस्र के लिए रवाना हो गई है। टीम के पिछले ग्लोबल इवेंट में हुई गलती के लिए हेड कोच पर लाइफटाइम बैन लगा दिया गया था। फेडरेशन ने किसी विदेशी कोच का इंतजाम नहीं किया है और इसके बजाय एक पाकिस्तानी कोच को नियुक्त किया है जिस पर 2023 में लाइफटाइम बैन लगा दिया गया था। टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी खिलाड़ी टीम के लिए अंतरिम इंतजामों से खुश नहीं हैं।

सूत्रों ने टेलीकॉम एशिया डॉटनेट को बताया, अम्माद बट की लीडरशिप में पाकिस्तान हॉकी खिलाड़ी टीम के अंतरिम इंतजामों से खुश नहीं हैं क्योंकि वे डचमैन रोलेंट ओल्टमैंस को हेड कोच बनाना चाहते थे, लेकिन नेशनल हॉकी के नए अंतरिम हेड ने ख्वाजा जुनैद को नियुक्त किया, जिन पर

2023 में लाइफटाइम बैन लगा दिया गया था। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतरिम अध्यक्ष मोहिउद्दीन वानी ने खिलाड़ियों की बात सुनी,लेकिन उन्हें जुनैद के साथ जाने की सलाह दी,क्योंकि वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए ओल्टमैंस को नियुक्त करने के लिए काफी समय नहीं था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कप्तान अम्माद बट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के चेयरमैन मोहसिन नकवी से दखल देने के लिए संपर्क किया,लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वह गृहमंत्री के तौर पर कुछ काम में व्यस्त थे।

विमेंस टी-20 वर्ल्डकप 2026 का शेड्यूल जारी

12 टीमें खेलेंगी 33 मुकाबले, पाकिस्तान के खिलाफ मैच से शुरू होगा भारत का अभियान

नई दिल्ली,24 फरवरी 2026। आईसीसी ने विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस बार टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें हिस्सा लेंगी, जो अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा हैं। मेजबान इंग्लैंड 12 जून को टूर्नामेंट के उद्घाटन मुकाबले में श्रीलंका से खेलेगा। टूर्नामेंट का 10वां एडिशन 12 जून से 5 जुलाई तक खेला जाएगा।

टीम इंडिया 14 जून को अपना अभियान इस टूर्नामेंट में शुरू करेगी। भारतीय टीम का पहला मुकाबला पाकिस्तान के साथ होगा। टीम इंडिया के ग्रुप में पाकिस्तान के अलावा ऑस्ट्रेलिया,साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और नीदरलैंड भी मौजूद हैं।

दोनों ग्रुप से टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी

आईसीसी ने 12 टीमों को 6-6 टीमों के 2 ग्रुप में बांटा है। इन दोनों ग्रुप की टॉप पर रहने वाली दो-दो टीमें सेमीफाइनल में क्वॉलिफाई करेंगी।

आईसीसी के सीईओ का बयान

आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता ने कहा, विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी होना, इस ग्लोबल प्रीमियर स्पोर्टिंग इवेंट से पहले एक अहम पड़ाव है। यह इवेंट

आईसीसी के विमेंस क्रिकेट में लगातार इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है, जिसमें ज्यादा भागीदारी और हाई-परफॉर्मेंस के तरीके, इवेंट और प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, टूर्नामेंट प्राइज मनी, मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन और कमर्शियल पार्टनरशिप शामिल हैं।

ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल टीम रही

विमेंस टी-20 वर्ल्ड कप के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल टीम रही है। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक रिकॉर्ड छह बार खिताब अपने नाम किया है और कई बार फाइनल तक पहुंचकर अपनी बादशाहत साबित की है। इसके अलावा इंग्लैंड ने 2009 में पहला एडिशन जीतकर इतिहास रचा, जबकि वेस्टइंडीज ने 2016 में खिताब जीता था।

रिंकू सिंह प्रैक्टिस से बाहर

चेन्नई,24 फरवरी 2026। भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते बल्लेबाज़ रिंकू सिंह चेन्नई में निर्धारित टीम प्रैक्टिस सत्र में शामिल नहीं हो सके। टीम सूत्रों के अनुसार, रिंकू सिंह पारिवारिक आपातस्थिति (फैमिली इमरजेंसी) के कारण अचानक घर लौट गए हैं। उनकी अनुपस्थिति से टीम प्रबंधन और प्रशंसकों के बीच हलचल देखी जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक,रिंकू सिंह को व्यक्तिगत कारणों से तत्काल रवाना होना पड़ा। हालांकि, टीम या खिलाड़ी की ओर से इमरजेंसी के विवरण को सार्वजनिक नहीं किया गया है। टीम मैनेजमेंट ने खिलाड़ी की निजता का सम्मान करते हुए स्थिति पर संयमित प्रतिक्रिया दी है और उम्मीद जताई है कि सब कुछ जल्द सामान्य होगा।

रिंकू सिंह हाल के समय में अपनी आक्रामक बल्लेबाज़ी और मैच फिनिशिंग क्षमताओं के कारण टीम के अहम सदस्य बनकर उभरे हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सत्र से उनका बाहर रहना रणनीतिक दृष्टि से टीम के लिए चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। कोचिंग स्टाफ फिलहाल अन्य खिलाड़ियों के साथ संयोजन पर काम कर रहा है, ताकि तैयारियों पर असर न्यूनतम रहे। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि पेशेवर खेलों में खिलाड़ियों की व्यक्तिगत परिस्थितियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं, जितनी मैदान पर उनकी भूमिका। टीम आम तौर पर ऐसे मामलों में पूर्ण सहयोग और लचीलापन दिखाती है। फिलहाल, रिंकू सिंह की वापसी को लेकर कोई आधिकारिक समयसीमा सामने नहीं आई है। टीम और फैंस उनकी जल्द वापसी और परिवार के लिए शुभकामनाएं व्यक्त कर रहे हैं।

सीसीआई ब्राबोर्न स्टेडियम में 2026 में इंडियन ओपन की मेजबानी की जाएगी

मुंबई,24 फरवरी 2026। इंडियन ओपन ने अपने आगामी 2026 संस्करण की तिथियों की घोषणा कर दी है, यह टूर्नामेंट 18-22 मार्च को मुंबई में आयोजित किया जाएगा। पिछले साल प्रतिष्ठित बॉम्बे जिमखाना में मिली सफलता के बाद, इंडियन ओपन की एक विज्ञप्ति के अनुसार, इस आयोजन का दूसरा संस्करण अब ऐतिहासिक सीसीआई ब्रेबोर्न स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन (पीएसए) द्वारा मान्यता प्राप्त, यह टूर्नामेंट अपने 2025 संस्करण की सफलता को आगे बढ़ाता है,जिसे वर्ष के शीर्ष 10 प्रतिष्ठित पीएसए आयोजनों में शामिल किया गया था, जो भारत में पेशेवर स्क्वैश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर पर इस आयोजन की बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाता है।

2026 संस्करण में महिला वर्ग की मौजूदा चैंपियन अनाहत सिंह मुख्य आकर्षण के रूप में वापसी करेंगी। 2026 के प्रतिभागियों में भारत के शीर्ष पेशेवर खिलाड़ी रमित टंडन,अभय सिंह, वीर चोटरानी,वेलवन सेंथिलकुमार और जोशना चिनप्पा के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी याह्या एलनावासानी,हाना मोअताज़,माज़ेन हेशम और अन्य शामिल हैं,जो विश्व स्तरीय स्क्वैश के एक बेहद प्रतिस्पर्धी सप्ताह के लिए मंच तैयार करते हैं।

इस वर्ष के संस्करण में पुरुष और महिला दोनों स्पर्धाओं के लिए 44,500 डॉलर की पुरस्कार राशि रखी गई है,जो भारत में आयोजित होने वाले किसी टूर्नामेंट के लिए एक और अभूतपूर्व उपलब्धि है। पीएसए कॉपर इवेंट होने के नाते,यह टूर्नामेंट पेशेवर स्क्वैश जगत में अपनी प्रतिष्ठा को और भी मजबूत करता है। जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के सीईओ दिव्यांशु सिंह ने कहा,पिछले साल के आयोजन को मिली प्रतिक्रिया से हम बेहद खुश हैं,जिसमें शीर्ष भारतीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी एक साथ आए और भारतीय स्क्वैश के बढ़ते स्तर को उजागर किया। लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक खेलों में स्क्वैश की ओलंपिक में पहली बार एंट्री होने के साथ,यह भारत में इस खेल के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है।

CMYK

SANKALP
CG Budget 2026-27
#छत्तीसगढ़_SANKALP_बजट

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने तीसरा बजट 'संकल्प' थीम पर प्रस्तुत किया.....

1.72 लाख करोड़ का बजट पेश

23 नए उद्योग खुलेंगे,बच्चियों को डेढ़ लाख,वन-संरक्षण के लिए 930 करोड़,कर्मचारियों का कैशलेस इलाज होगा

रायपुर,24 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए बस्तर और अन्य पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, डिजिटल कनेक्टिविटी और रोजगार का बड़ा रोडमैप सामने रखा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने साय सरकार का तीसरा बजट संकल्प थीम पर प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बजट 2026-27 को जनकल्याण और विकास को समर्पित बताते हुए कहा कि यह बजट किसानों,महिलाओं,युवाओं और कर्मचारियों के सशक्तिकरण के साथ छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि कृषि, उद्योग,स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर विशेष प्रावधानों से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और आम जनता के जीवन स्तर में सुधार आएगा। सरकार ने इस वर्ष कुल व्यय 1.72 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया है, जिसमें राजस्व व्यय 1.45 लाख करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय 26,500 करोड़ रुपए रखा गया है। पूंजीगत व्यय में वृद्धि से सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसी स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण को गति मिलेगी, जिससे प्रदेश में विकास कार्यों को मजबूती मिलेगी। बजट में पूंजी निवेश के लिए केंद्र से मिलने वाली विशेष सहायता को 4,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 8,500 करोड़ रुपए किया गया है, जिससे बड़े बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। वहीं राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 2.87 प्रतिशत पर नियंत्रित रखा गया है,जो संतुलित वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है और राज्य की मजबूत आर्थिक स्थिति का संकेत देता है। इस बार छत्तीसगढ़ के बजट में सामाजिक क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता देते हुए कुल व्यय का 40% प्रावधान किया गया है, जबकि आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए 36% और प्रशासनिक व सामान्य सेवाओं के लिए 24% राशि निर्धारित की गई है। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण और सतत् विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 14,300 करोड़ रुपए का विशेष ग्रीन बजट का भी प्रावधान किया गया है। बजट में सरगुजा,बस्तर और अन्य पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास को केंद्र में रखा गया है। बस्तर क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए अबूझमाड़ और जगरगुंडा जैसे अत्यंत संवेदनशील इलाकों में दो 'एजुकेशन सिटी' स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। खेल और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने विशेष प्रावधान किए हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसी पहलों के लिए बजट में संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि स्थानीय प्रतिभाओं को मंच मिल सके और क्षेत्र की सकारात्मक पहचान मजबूत हो। इसके साथ ही बस्तर फाइटर्स के 1500 नवीन पदों का सृजन किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर भी सरकार ने खास ध्यान दिया है। जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज एवं मेडिकल सिटी की स्थापना की घोषणा की गई है। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में डॉक्टरों की विशेष भर्ती की जाएगी, ताकि दूरस्थ इलाकों के लोगों को गुणवत्तापूर्ण उपचार अपने ही क्षेत्र में मिल सके। सिंचाई क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाते हुए इंद्रावती नदी पर लगभग 2024 करोड़ रुपये की लागत से बैराज निर्माण की योजना घोषित की गई है। इससे बस्तर क्षेत्र में लगभग 32 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने का अनुमान है।

महिलाओं को पंजीयन शुल्क में छूट,बालिकाओं को 1.5 लाख

छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 में महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने महिलाओं के नाम से संपत्ति क्रय पर लगने वाले पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देने का प्रस्ताव रखा है, जिससे महिलाओं को संपत्ति में स्वामित्व और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 'रानी दुर्गावती योजना' शुरू की जाएगी,जिसके तहत 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पात्र बालिकाओं को 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसक साथ ही 'मुख्यमंत्री लखपति दीदी भ्रमण योजना' लागू की जाएगी,वहीं उनके सामाजिक सशक्तिकरण के लिए 250 महतारी सदनों के निर्माण का प्रावधान किया गया है।

कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना

बजट में शासकीय कर्मचारियों के स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कैशलेस चिकित्सा योजना लागू करने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को उपचार के दौरान अस्पताल में नकद भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

5 नालंदा लाइब्रेरी के लिए 22 करोड़ का प्रावधान

मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना लागू होगी 200 करोड़ बजट का प्रावधान शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान योजना के माध्यम से सरकार और गैर सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए 5 लाख रू तक की इलाज के लिए डेढ़ हजार करोड़ का प्रावधान ।

बच्चियों को 18 साल पूरे होने पर डेढ़ लाख मिलेंगे

रानी दुर्गावती योजना का ऐलान, बच्चियों के 18 साल पूरे होने पर डेढ़ लाख रू की राशि दी जाएगी। शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान योजना के माध्यम से सरकार और गैर सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए 5 लाख रू तक की इलाज के लिए डेढ़ हजार करोड़ का प्रावधान ।

नए मेडिकल कॉलेज

बजट में छत्तीसगढ़ में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान भी किया गया है। वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि दंतेवाड़ा,मनेंद्रगढ़,कबीरधाम,जांजगीर-चांपा और कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा रायपुर के कालीबाड़ी में 200 बिस्तरों वाला एमसीएच तथा चिरमिरी में जिला अस्पताल के निर्माण का प्रावधान किया गया है।

अन्य प्रमुख घोषणाएं

- 50 लाख रुपए तक के विकास कार्य ग्राम सभा के माध्यम से कराए जाएंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर निर्णय और क्रियान्वयन को बढ़ावा मिलेगा।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1700 करोड़ रुपए का प्रावधान, जिससे ग्रामीण सड़कों का विस्तार और कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
- मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट, जिससे राज्य में सड़क नेटवर्क को और बेहतर बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को बताया 'संकल्प से सिद्धि' का रोडमैप

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास, अंत्योदय और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ के निर्माण के संकल्प को साकार करने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का पहला बजट 'ज्ञान' और दूसरा बजट 'गति' की थीम पर आधारित था, जबकि इस वर्ष का बजट 'संकल्प' की भावना को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है, जो विकसित भारत-विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में निर्णायक कदम सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस बजट में समावेशी विकास, अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण, निवेश संवर्धन, कुशल मानव संसाधन निर्माण, लाइवलीहुड, अंत्योदय तथा 'पॉलिसी से परिणाम' तक की स्पष्ट रणनीति को प्राथमिकता दी गई है। यह बजट यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप प्रदेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार मिशन मोड में कार्य करने के लिए पांच मुख्यमंत्री मिशन प्रारंभ कर रही है, जिनमें मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन, मुख्यमंत्री एआई मिशन, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, मुख्यमंत्री स्टार्टअप मिशन तथा मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन शामिल हैं। इन मिशनों के माध्यम से प्रदेश के विकास को नई दिशा, नई धार और नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्कूल शिक्षा के लिए कुल बजट का 13.5 प्रतिशत प्रावधान किया गया है, जो सर्वाधिक है। बस्तर के अबूझमाड़ और जगरगुंडा में दो एजुकेशन सिटी स्थापित की जाएंगी, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार सुविधा हेतु भी बजट में प्रावधान किया गया है। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 23 नवीन औद्योगिक पार्कों की स्थापना हेतु 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना में 200 करोड़ रुपए तथा भूमि विकास बैंक के लिए भी 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और कृषि क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। इसी को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र के लिए 13 हजार 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी के अंतर की राशि का भुगतान एकमुश्त करने की व्यवस्था जारी रहेगी और इसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर और सरगुजा क्षेत्र का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इन क्षेत्रों में खाद्य, कृषि और उससे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही बकरी पालन, सूअर पालन और मधुमक्खी पालन जैसे गतिविधियों को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इंद्रावती नदी पर देवरगांव और मटनार बैराज निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है, जिससे बस्तर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का विस्तार होगा और किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि माओवादी उन्मूलन में बस्तर फाइटर्स की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

मजदूर,महिला, किसान,युवा पर केंद्रित बजट

जी राम जी योजना के लिए 4000 करोड़ का प्रावधान। युवाओं के लिए कुल 1,097 करोड़ का प्रावधान। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना के लिए 60 करोड़ का प्रावधान। गन्ना किसानों को बोनस के लिए 60 करोड़ का बजट प्रावधान।छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान। महिलाओं के नाम पर भूमि,भवन,अचल संपत्ति क्रय पर भारित पंजीयन शुल्क पर मिलेगी 50 प्रतिशत की छूट। 6500 करोड़ के प्रावधान से हर जरूरतमंद तक खाद्य सुरक्षा पहुंचेगी। मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के तहत पांच वर्षों तक प्रतिवर्ष 100 करोड़ का बजट प्रावधान।

अधोसंरचना और विकास के लिए ऐलान

आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। रायपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए 200 सीट का छात्रावास बनेगा,साथ ही बस्तर को शिक्षा का केंद्र बनाने पर जोर है। मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बस्तर-सरगुजा विकास के लिए बड़े प्रावधान हैं,जिसमें मटनार और देवरगांव बैराज निर्माण के लिए 2024 करोड़ रुपये शामिल हैं। मुख्यमंत्री एआई मिशन, पर्यटन विकास मिशन,खेल उत्कर्ष मिशन,अधोसंरचना मिशन और स्टार्टअप मिशन भी शुरू किए जाएंगे।

नए औद्योगिक पार्कों का ऐलान

बजट में 23 नए औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है,जिसके लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से औद्योगिक विकास मद में 100 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

बजट में कृषि क्षेत्र के लिए प्रावधान

सरकार ने 'कृषक उन्नति योजना' के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे किसानों को आर्थिक सहायता और कृषि विकास को गति मिलेगी। कृषि पंपों के लिए 5,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर सिंचाई सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा, वहीं भूमिहीन कृषि परिवारों के समर्थन के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग, एग्रो-फॉरेस्ट प्रोसेसिंग, राइस मिल और पोल्ट्री फार्म जैसे रोजगारमूलक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिससे किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने में मदद मिलेगी।

बजट में इस बार दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट के दौरान कहा कि डेयरी समग्र विकास योजना के अंतर्गत 90 करोड़ का प्रावधान किया गया है। समावेशी, सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्वहितकारी विकास की दिशा में सुशासन सरकार का सशक्त कदम है। हर वर्ग के लिए नए अवसरों का सृजन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाओं और बजट प्रावधानों के माध्यम से हर स्तर पर विकास कार्य किया गया है।

पर्यटन से विकास को मिलेगी गति

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश करते हुए कहा कि इस बार के बजट में मैनपाट के पर्यटन विकास के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

प्रमुख शहरों के एयरपोर्ट

पांच प्रमुख शहरों के एयरपोर्ट पर छत्तीसगढ़ी उत्पादों का शोरूम खोलने की भी घोषणा की गई है।

लड़कियों के लिए बड़ा ऐलान

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की लड़कियों के लिए भी बजट में बड़ा ऐलान किया है। 18 साल पूरे होने पर बच्चियों को डेढ़ लाख रुपए की राशि देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना को रानी दुर्गावती योजना नाम दिया गया है।

स्कूल शिक्षा विभाग

स्कूल शिक्षा विभाग के लिए बजट में इस बार सरकार ने बड़ी राशि का प्रावधान किया है। 22 हजार करोड़ की राशि स्कूल शिक्षा विभाग के लिए खर्च किए जाएंगे, जिसके तहत अलग-अलग जिलों में प्राइमरी और हाई स्कूलों का निर्माण किया जाएगा।

बैराज निर्माण

वहीं बस्तर के लिए एक और बड़ा ऐलान किया गया है। जहां बस्तर में इंद्रावती नदी पर मटनार एवं देउरगांव बैराज के निर्माण के लिए 2,024 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह बैराज निर्माण भी अहम माना जा रहा है।

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा...'ज्ञान' और 'गति' के 'संकल्प' से विकसित छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ता ऐतिहासिक बजट

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ के बजट 2026-27 को प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में दूरदर्शी, संतुलित और विकासोन्मुख बजट बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि 'ज्ञान' और 'गति' के संकल्प के साथ विकसित छत्तीसगढ़ की सशक्त कार्ययोजना है। उन्होंने बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए 16 हजार 5 करोड़ रुपये से अधिक और गृह विभाग के लिए 8,380 करोड़ रुपये का प्रावधान राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है। शिक्षा, कौशल विकास, अधोसंरचना, निवेश, अंत्योदय, आजीविका और कुशल मानव संसाधन निर्माण पर केंद्रित यह बजट सर्वस्पर्शी विकास का प्रतीक है। आवासहीनों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना एवं विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए 4-4 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान राज्य की संवेदनशील और प्रतिबद्ध सरकार का प्रमाण है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सशस्त्र नक्सलवाद के प्रभाव से उबरते बस्तर में अब विकास की नई धारा बहेगी। 1500 बस्तर फाइटर्स की भर्ती स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। अबूझमाड़ और जगरगुंडा में 100 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित होने वाली एजुकेशन सिटी क्षेत्र के शैक्षणिक परिदृश्य को नई दिशा देगी। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए के सड़क निर्माण और 200 करोड़ रुपए के आवास निर्माण के लिए और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान जनजातीय अंचलों के समग्र उत्थान का मार्ग प्रशस्त करेगा। सीजी एसीई योजना के लिए 33 करोड़ रुपये का प्रावधान कर राज्य सरकार ने नीट, जेईई, क्लैट, यूपीएससी, सीजीपीएससी, रेलवे और बैंकिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को मजबूत आधार दिया है। मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों को रेंटल आवास सुविधा के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान सामाजिक न्याय और समान अवसर की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

रायपुर, बिलासपुर,दुर्ग सहित कवर्धा, रायगढ़,जशपुर और जगदलपुर में नए सीजीआईटी संस्थानों के लिए 38 करोड़ रुपये और 36 सीजी इनोवेशन केंद्र एवं एसटीपीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान युवाओं को तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में नई ऊर्जा देगा।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)